वर्ष ४ अंक ११ नवंबर १९८२ १ रु.

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

युद्ध और मजदूर वर्ग

बी टी रणदिवे

एक सितम्बर को युद्ध-विरोधी दिवस मनाने के सीटू के आह्वान पर पश्चिम बंगाल में विशाल शांति आंदोलन और सभी राज्यों मे आयोजित बड़े शांति प्रदर्शन तथा जो छः राजनीतिक पार्टियों के आह्वान पर ४ अक्तूबर को एक विशाल शांति रैली में बदल गए, न्यूक्लीयर विश्वयुद्ध के खतरे के साइज का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय जनता के प्रथम आंदोलन है।

यह कोई अचानक नहीं है कि इन सभी रैलियों में मजदूर वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। और यह भी कोई अचानक नहीं है कि वामपंथी पार्टियां, खासतौर से सी पी आई (एम) व सी पी आई, इन प्रतिरोधों का नेतृत्व कर रही है और उन्होंने सभी राज्यों में उन्हें संगठित करने की जिम्मेदारी उठाई है।

दसियों हजार लोगों ने विभिन्न राज्यों में आयोजित रैलियों में भाग लिया और न्यूक्लीयर युद्ध के खतरे तथा न्यूक्लीयर युद्ध को भड़काने वाले के रूप में अमरीकी साम्राज्य को कसूरवार ठहराए जाने को ध्यान से सुना।

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विजयवाड़ा, बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम व कई अन्य राज्यों की राजधानियों में विशाल रैलियां आयोजित हुई। आंध्र प्रदेश में अनेक तहसीलों में एक सितम्बर को शांति रैलियां आयोजित की गईं।

बुर्जुवा-जमींदार पार्टियों की भूमिका

विश्व की जनता के सामने इस संकट के दौर में यह नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में बुर्जुवा जमींदार पार्टियों ने, शासक व विपक्षी दोनों ही, इस विषय में कुछ भी नहीं किया, वे इस प्रकार काम करती हैं जैसे कि युद्ध का खतरा है ही नहीं, जैसे कि विश्व को नरसंहार का खतरा ही न हो, और जैसे कि भारत की स्वतंत्रता व आजादी को खतरा न हो।

कभी-कभी सरकार शांति को खतरे के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है, लेकिन यह केवल एक औपचारिक प्रतिरोध ही है। शासक पार्टी जनता के पास नहीं जाती है, या अपना पूरा जोर व प्रसाधनों को इस विश्व खतरे के खिलाफ जनता को लामबंद करने में नहीं लगाती है। इसका दो महाशक्ति का सिद्धांत और इस द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद को बेनकाब करने के लिये तैयार न होना युद्ध के खिलाफ संघर्ष को ठप्प कर देता है। ऐसा लगता है कि बुर्जुवा विपक्षी पार्टियां—कांग्रेस (एस), जनता पार्टी, लोकदल या तमिलनाडु में डी एम के या ए आई डी एम के—विश्व और हमारे देश के भाग्य से कोई सरोकार नहीं रखती हैं। वे चुनावी लड़ाई में अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए फौरी जोड़-तोड़ पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं। ऐसा संकीर्ण स्वार्थीपन ही बुर्जुवा पार्टियों का प्रमाण-चिन्ह है। भारतीय ग्रामीण जनता के सम्बन्ध में बहुत पहले मार्क्स ने कहा था :

"हमें इस समुदाय की बर्बरस्वार्थपरता को हरगिज नहीं भूलना चाहिए—वह भूमि के एक तुच्छ टुकड़े के साथ चिपटा हुआ, चुपचाप साम्राज्यों की तबाही देखता रहा, अकथनीय जुल्म होते देखता रहा, बड़े-बड़े नगरों की सारी आबादी का कत्लेआम भी देखता रहा, इस तरह जैसे प्राकृतिक घटनाएं देख रहा हो, और जो स्वयं इतना लाचार था कि जिस किसी आक्रमणकारी की नजर में वह पड़ गया उसका निःसहाय भाव से शिकार हो गया।" (मार्क्स-एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खंड-१, भाग-२, पृष्ठ २५२)। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी स्वार्थपरता को फिर दोहराया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जो बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर कांग्रेस (आई) का विकल्प माने जाने का अपना दावा कर रही है, इस मुद्दे पर चुप है। जब राष्ट्रपति ब्रेझनेव भारत आए थे, उस

कोयला खदान मजदूरों की हड़ताल : ८ नवंबर

का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में उठाए गये सोवियत कदमों के खिलाफ प्रतिरोध में एक प्रदर्शन करना भी यह नहीं भूली। लेकिन अब भी जब अमरीकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, जब रीगनप्रशासन के साथ सांठगांठ करके लेबनान पर इस्राइली आक्रमण तथा फिलिस्तीनियों का कत्लेआम किया गया है, तब भी यह पार्टी चुप है। अमरीकी साजिशों के खिलाफ यह न तो प्रतिरोध करती है और न ही करेगी। गहरे सैद्धांतिक व अन्य सम्बन्ध इसे अमरीका तथा इसकी करतूतों के साथ बांधते हैं। विश्व-खतरे के प्रति बुर्जुवा-जमींदार पार्टियों की यह उदासीनता और इसके साथ-साथ ही इस खतरे का मुकाबला करने के लिए मजदूर वर्ग और जनता को सक्रिय बनाना दो भिन्न दृष्टिकोणों को पेश करते हैं।

मजदूर वर्ग की भूमिका

अपने जन्म से ही मजदूर वर्ग ने दूसरे देशों में अपने वर्ग-भाइयों व मेहनतकशों के प्रति अपनी एकजुटता की गहरी भावना के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित किया है। इसके विकसित हिस्से, जो मार्क्स और एंगेल्स व लेनिन द्वारा प्रशिक्षित किए गए, अपनी सरकारों द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का जायजा लेने के लिए हमेशा अपने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को इस्तेमाल करते हैं और राष्ट्रों के बीच युद्ध तथा विवाद पर अपनी राय कायम करते हैं। देश-भक्ति का छल कर रहा राष्ट्रीय कट्टरपंथ इस दृष्टिकोण का शत्रु है। यह दृष्टिकोण समाजवाद के आम लक्ष्यों के लिए एकजुटता पर और विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता करने पर आधारित है। यह बस केवल शांतिवादी नहीं है बल्कि यह उस सिलसिले पर जिसमें युद्ध लड़ा जा रहा है और हर युद्ध के चरित्र या दोनों भागीदारों के लिए एक खास युद्ध के विभिन्न चरित्र पर आधारित है।

प्रथम इंटरनेशनल

मार्क्स ने १८६४ में इंटरनेशल वर्किंगमेन्ज एसोसिएशन (प्रथम इंटरनेशनल) के उद्घाटन भाषण में विदेश नीति के मामलों के प्रति एसोसिएशन के दृष्टिकोण की रचना इन शब्दों में की—"यदि मजदूर वर्ग की मुक्ति के लिए यह आवश्यक है कि मजदूरों में भ्रातृत्वपूर्ण मतैक्य हो, तो वे अपना यह महान उद्देश्य मुजरिमाना मंसूबों पर आश्रित ऐसी विदेश नीति के रहते हुए किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों का स्वार्थपूर्ण उपयोग किया जाता है और लुटेरे युद्धों में जनता का खून और धन पानी की तरह बहाया जाता है?" इंटरनेशनल जिस विदेश नीति को अपना लक्ष्य मानता है उसकी परिभाषा इन शब्दों में की गई—"व्यक्तियों के जाति सम्बन्ध नैतिकता तथा न्याय के जिन सीधे-सादे नियमों द्वारा निर्देशित होने चाहिएं, उन्हीं का राष्ट्रों के परस्पर संसर्ग में प्रधानतम नियमों के रूप में पालन किया जाए।"

बस युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का आह्वान नहीं था।

फ्रांसीसी प्रशा युद्ध

मजदूर वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परीक्षण १८७० के फ्रांसीसी-प्रशा युद्ध में हुआ। इसे यूरोपीय स्थिति व विकास के रूप में समझा गया।

'सभी राष्ट्रों के मेहनतकशों' के नाम इंटरनेशल के पेरिस सदस्यों ने एक घोषणा जारी की जिसमें कहा गया, "यूरोपीय संतुलन के नाम पर, राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर एक बार फिर विश्वशांति राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं द्वारा खतरे में डाल दी गई है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के मजदूरो! आओ, हम सब एक स्वर में युद्ध के खिलाफ उसे धिक्कारते हुए आवाज उठाएं···जर्मनी के भाइयो! यदि हम विभक्त रहे तो उसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि राइन नदी के दोनों ओर निरंकुशता की पूर्ण विजय होगी···प्रत्येक देश के मजदूरो! हमारे सम्मिलित प्रयासों का इस समय चाहे जो भी नतीजा निकले, हम, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य, जो किसी राज्यीय सीमा के बंधे हुए नहीं हैं, अपनी अटूट एकजुटता के प्रतीक स्वरूप आपको फ्रांस के मजदूरों की शुभकामनाएं और अभिवादन भेजते हैं।" (मार्क्स, एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खंड-२, भाग १, पृष्ठ २५१-५२)।

साथ ही इंटरनेशनल वर्किंगमेंस एसोसिएशन की जनरल काउंसिल के पहले वक्तव्य ने घोषणा की कि, "जर्मनी के लिए युद्ध प्रतिरक्षात्मक युद्ध है, लेकिन जर्मनी को अपनी रक्षा करने की जरूरत पर किसने लाकर खड़ा किया? उस पर हमला करने के लिए लुईस बोनापार्टा को योग्य किसने बनाया? प्रशा!" मार्क्स जर्मनी के शासकों को बेनकाब करना नहीं भूले, लेकिन उसी समय उन्होंने इस तथ्य को उभारा कि जर्मनी के लिए युद्ध प्रतिरक्षात्मक युद्ध है। इस युद्ध के संबंध में लेनिन ने अपने लेख समाजवाद व युद्ध में कहा कि, "फ्रांस और प्रशा के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को लूटा, लेकिन इस बात में उस युद्ध के बुनियादी ऐतिहासिक महत्व में कोई अंतर नहीं पैदा होता, जिसने लाखों लाख जर्मनों को सामंती बंटवारे तथा दो स्वेच्छाचारी शासकों रूसी जार और नेपोलियन तृतीय— के उत्पीड़न से मुक्त किया!" (समाजवाद और युद्ध, लेनिन, पृष्ठ-८ एवं खंड २१ (अंग्रेजी), पृष्ठ ३००)।

फ्रांसीसी या जर्मनी के मजदूर वर्ग के मामले में यह कुल मिलकर बस युद्ध विरोधी स्थिति थी। इन दो हिस्सों को युद्ध के चरित्र पर उस नजरिये से विचार करना पड़ा कि ये उन पर किस प्रकार असर डालती थीं।

इसलिए जर्मन मजदूर वर्ग ने फ्रांसीसी मजदूरों की अपील का बूसमिक में संपन्न एक बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव में इन शब्दों में जवाब दिया, "हम हर प्रकार के युद्ध के दुश्मन हैं, पर सबसे अधिक राजवंशीय युद्धों के दुश्मन हैं···एक अनिवार्य बुराई के रूप में हम प्रतिरक्षात्मक युद्ध गहरे विषाद एवं शोक के साथ सहन करने को

विवश हैं, किंतु साथ ही हम समस्त जर्मन मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं कि वह हरेक जनगण को स्वयं युद्ध और शांति का निर्णय करने का अधिकार उपलब्धि कराके तथा उन्हें अपने भाग्य का खुद मालिक बनाकर युद्ध जैसी भीषण सामाजिक विपत्ति की पुनरावृति असंभव बना दे।" (मार्क्स एवं एंगेल्स, संकलित रचनाएं, खंड २, भाग १, पृष्ठ २५३-२५४)।

जनरल काउंसिल ने जर्मन मजदूर वर्ग को चेतावनी दी कि, "यदि जर्मनी का मजदूर वर्ग मौजूदा युद्ध को अपना सर्वथा प्रतिरक्षात्मक चरित्र खोकर फ्रांसीसी जनता के विरुद्ध युद्ध का पतित रूप धारण करने देगा, तो जीत और हार दोनों समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होंगी। जर्मनी के ऊपर उसके स्वातंत्र्य-युद्ध के बाद मुसीबतों का जो पहाड़ टूटा था, वह कहीं अधिक भीषणता के साथ उसके ऊपर फिर टूट पड़ेगा।" (पृष्ठ २५३, वही)

सही समझ

शांतिवादी या बस युद्धविरोधी दृष्टिकोण युद्ध के बारे में मार्क्सवादी समझ का गुण कभी नहीं रहा। कुछ युद्धों के प्रगतिवादी चरित्र को मार्क्सवादियों-लेनिनवादियों ने समझा है और प्रशंसा की है और उन्होंने प्रगतिवादी पक्ष की विजय के लिए कार्य किया है। लेनिन लिखते हैं, "महान फ्रांसीसी क्रान्ति ने मानवजाति के इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात किया। उस समय से पेरिस कम्यून तक, १७८९ से १८७१ तक एक किस्म के युद्ध वे रहे, जिनका चरित्र पूंजीवादी-प्रगतिशील और राष्ट्रीय-मुक्तिकारी था। दूसरे शब्दों में, उन युद्धों का मुख्य अन्तर्य तथा ऐतिहासिक महत्व निरंकुश सत्ता और सामंतशाही का उलटा जाना, उनका उन्मूलन, विदेशी उत्पीड़न का तख्ता उलटा जाना था। इसलिये वे प्रगतिशील युद्ध थे और ऐसे युद्धों के दौरान सभी ईमानदार क्रान्तिकारी जनवादी और त्योंही सभी समाजवादी भी हमेशा उस देश (यानी उस पूंजीपति वर्ग) के साथ हमदर्दी रखते थे, जिसने सामंतशाही, निरंकुश सत्ता और दूसरे राष्ट्रों के उत्पीड़न की सबसे अधिक खतरनाक बुनियादों को तहो-बाला करने या खोदने में सहायता पहुंचाई···समाजवादियों ने केवल इसी अर्थ में "पितृभूमि की प्रतिरक्षा" को अथवा "प्रतिरक्षात्मक" युद्धों को उचित, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण माना है और अब भी मानते हैं। मिसाल के लिये, अगर कल मोरक्को फ्रांस के खिलाफ, या भारत ब्रिटेन के खिलाफ, या ईरान अथवा चीन रूस के खिलाफ, इत्यादि, इत्यादि, युद्ध की घोषणा कर दे, तो पहले हमला चाहे जो भी करे, वे युद्ध 'न्याय्य', "प्रतिरक्षात्मक" युद्ध होंगे···।" (समाजवाद और युद्ध, लेनिन, पृष्ठ ८-९, एवं खंड २१ (अंग्रेजी), पृष्ठ २९९-३००)।

ऐसे युद्धों में कम्युनिस्ट पक्षपाती दृष्टिकोण अपनाते हैं और प्रगतिवादी पक्ष की सफलता के लिये कार्य करते हैं।

साम्राज्यवादी युद्ध

लेकिन लेनिन के जमाने में विश्व के विभाजन के लिए साम्राज्यवादी ताकतों के बीच संघर्ष पहले ही शुरू हो चुका था। इस होड़ से उत्पन्न प्रथम विश्वयुद्ध को लेनिन ने साम्राज्यवादी युद्ध, दुनिया के लुटेरों के बीच युद्ध करार किया। इस युद्ध में कोई प्रगतिवादी पक्ष नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा का कर्तव्य था अपनी ही सरकार के साथ लड़ना न कि पितृभूमि की प्रतिरक्षा के नाम पर इसे समर्थन देना, अपनी ही साम्राज्यवादी सरकार की पराजय के लिए कार्य करना और बिना क्षेत्रवृद्धि के शांति की स्थापना करना। लेनिन ने उन सभी की, जिन्होंने साम्राज्यवादी युद्ध का समर्थन किया, यह कहकर निंदा की कि वे समाजवाद के लक्ष्य के प्रति विश्वासघाती हैं। क्रांतिकारी नीतियों पर रूसी सर्वहारा का नेतृत्व करते हुए लेनिन के मार्गदर्शन में एस० डी० पी० ने युद्ध के खात्मे के लिए कार्य किया और जार का तख्ता पलटने में और बाद में सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व करने में सफलता हासिल की।

पहले विश्वयुद्ध में युद्ध के सवाल पर संशोधनवादी और क्रांतिकारी विभाजित थे जबकि संशोधनवादी युद्ध का समर्थन कर रहे थे और क्रांतिकारी मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिक्रियावादी युद्ध का विरोध कर रहे थे और साम्राज्यवादी सरकार को क्रांतिकारी ढंग से उखाड़ फेंकने के लिए कार्य कर रहे थे। यहां भी मजदूर वर्ग ने बस मात्र शांतिवादी दृष्टिकोण, युद्ध को समर्थन नहीं का दृष्टिकोण नहीं अपनाया, बल्कि युद्ध के सामाजिक महत्व—विश्व के विभाजन—का जायजा लिया और अपने रोष को जंगबाज सरकारों के खिलाफ मोड़ा। "समाजवादियों ने राष्ट्रों के आपसी युद्धों को बर्बर और पाशविक कृत्य कहकर हमेशा उनकी निंदा की है। लेकिन युद्ध के प्रति हमारा रुख पूंजीवादी शांतिवादियों (शांति के पक्षपातियों और प्रचारकों) तथा अराजकतावादियों के रुख से मूलतः भिन्न है···हम मार्क्सवादी लोग शांतिवादियों तथा अराजकतावादियों दोनों से इस मानी में मतभेद रखते हैं कि हम हर युद्ध का ऐतिहासिक (मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से) अध्ययन करना जरूरी समझते हैं।" (समाजवाद और युद्ध, लेनिन, पृष्ठ ७ और खंड २१ (अंग्रेजी,) पृष्ठ-२९९)।

समाजवाद परिवर्तन लाता है

जाहिर है कि सोवियत संघ के जन्म से, सोवियत संघ में पहले समाजवादी राज्य की स्थापना से स्थिति में परिवर्तन आया है। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद अब साम्राज्यवादी गठबंधनों के युवा समाजवादी राज्य के खिलाफ हमलों से प्रतिरक्षा व अनुरक्षण से संबंधित थे। यूरोप के युद्ध से थके मजदूर वर्ग ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाई और साम्राज्यवादियों को नये समाजवादी राज्य के खिलाफ अपनी हस्तक्षेपी कोशिशों से पीछे हटते पाया।

करने के लिए अफगानिस्तान में उठाए गये सोवियत

बस युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का आह्वान नहीं था।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले के समूचे दौर में और खास तौर से जर्मनी में फासीवाद के जन्म के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दो नीतियों में विवाद पाया गया—समाजवादी राज्य द्वारा अपनाई गई निरस्त्रीकरण व शांति की नीति और साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अपनाई गई पुनरस्त्रीकरण और शांति से भागने तथा बाद में युद्ध तैयारियों की नीति। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग और प्रगतिवादी ताकतों ने समाजवादी राज्य द्वारा अपनाई गई राष्ट्रों के बीच शांति की नीति का समर्थन किया।

जाहिर है कि सोवियत संघ के उत्थान और जर्मनी में नाजियों द्वारा सत्ता हथियाने ने सामूहिक सुरक्षा के सवाल को सबसे ऊपर ला दिया। समाजवादी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग ने नाजी जंगबाजों के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा का—फासीवादी युद्ध योजनाओं के विरोधी सभी देशों का गठबंधन—आह्वान किया।

नाजी समाजवादी राज्य के खिलाफ एक युद्ध की तैयारी कर रहे थे और मजदूर वर्ग बस केवल शांतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता था, वह दृष्टिकोण जो दोनों पक्षों पर दोष लगाकर निष्पक्षता जाहिर करने का है। इसका पक्षपाती और क्रांति की रक्षा से संबंधित होना लाजिमी है।

दूसरे विश्वयुद्ध के प्रति दृष्टिकोण

दूसरे विश्वयुद्ध के चरित्र की परख के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन ने इसके दो चरणों में दो भिन्न दृष्टिकोण अपनाये।

पहला चरण था एक ओर जर्मनी और दूसरी ओर फ्रांस व ब्रिटेन के बीच युद्ध। इसे साम्राज्यवादी ताकतों में प्रभुत्व के लिए विवाद के रूप में ठीक ही समझा गया था। यह इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सोवियत संघ के खिलाफ हिटलर को भड़काने की ब्रिटिश योजना फिलहाल नाकामयाब हो गई थी।

दूसरा चरण था सोवियत संघ के खिलाफ हिटलर का युद्ध। यह समाजवादी क्रांति व विश्व प्रगति के खिलाफ हमला था। इसे जनयुद्ध का नाम ठीक ही दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन ने हिटलर की हार और फासिस्ट-विरोधी गठबंधन की सफलता के लिए ठोस कार्य किया।

इस सही समझ का परिणाम था एक तिहाई दुनिया का समाजवादी दुनिया के रूप में उभरना, पुरानी उपनिवेशिक प्रणाली का पतन और स्वतंत्रता, शांति व समाजवाद के लिए कटिबद्ध ताकतों के समर्थन में वर्ग ताकतों के संतुलन में परिवर्तन। समाजवादी दुनिया और स्वतंत्रता व समाजवाद के भविष्य के बहुत ही नाजुक हालात में आज जब भारत के मजदूर वर्ग का सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को बुलंद करने के लिए आह्वान किया जा रहा है, इन सब बातों को याद करना जरूरी है। यह और भी जरूरी इसलिए है क्योंकि बुर्जुवा नेताओं या समाजवादी खेमे के विरोधियों या राजनीति के उग्रपंथियों के रूप में सक्रिय सोवियत-विरोधी तत्वों द्वारा हर तरह के शांतिवादी व निष्पक्ष कदमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भारतीय मजदूर वर्ग जिसकी सर्वहारा चेतना कमजोर है इन तत्वों द्वारा गलत-मार्गदर्शन का शिकार हो सक.. है।

मौजूदा संदर्भ में

जिस युद्ध की तैयारी हो रही है उसके चरित्र को पूरी तरह समझा जाना चाहिए। इसकी तैयारी अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा की जा रही है और वे सब जो दो महाशक्तियों की बात करते हैं और जो साम्राज्यवादी शक्ति को एक समाजवादी देश के समान ठहराते हैं पाखंडी हैं। खास तौर से नक्सलवादी सोवियत संघ को सामाजिकसाम्राज्यवादी ताकत कहकर अमरीकीसाम्राज्यवाद की सहायता करते हैं, उनका कहना है कि सोवियत संघ के प्रति कोई भी पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। दो महाशक्तियों के भ्रम की तरह यह दृष्टिकोण भी हमारे देश में लाखों-लाख लोगों को निष्क्रिय करके साम्राज्यवादियों की ही सहायता करता है जबकि इन लोगों को एक समाजवादी देश के खिलाफ युद्ध योजनाओं के खिलाफ सक्रियता के साथ संघर्षरत होना चाहिए।

एक समाजवादी देश के खिलाफ अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा युद्ध की तैयारी की जा रही है। समूचा अस्त्रागार सोवियत संघ के खिलाफ केंद्रित है। जर्मन भूमि से सोवियत क्षेत्रों पर सीधे निशाने लगाने के लिए यूरोप में परशिंग व क्रूज मिसाइल लगाए गए हैं। इसका इरादा है समाजवादी देशों और विश्व मजदूर वर्ग आंदोलन के सभी लाभों को नष्ट करना तथा समूची दुनिया पर साम्राज्यवादी प्रभुता के साथ ताकतों के पुराने संतुलन को बहाल करना। समाजवादी शक्ति को नष्ट करने के बाद का इरादा है समूची दुनिया पर सर्वोच्च अमरीकी प्रभुता के साथ पुरानी उपनिवेशिक प्रणाली को फिर से कायम करना। यह बाद वाला इरादा तो पहले ही पश्चिम एशिया में इस्राइल जैसे दलालों के माध्यम से अरब जनता को अधीन करने के लिए कोशिशों व नरसंहारों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, यही चिली में देखा गया, सल्वाडोर में देखा गया—समूचे लैटिन अमरीका में, दक्षिण-पूर्वी ऐशिया में देखा गया और यह हिंद महासागर में जल न्यूक्लीयर अड्डों की स्थापना में देखा गया।

पाकिस्तान का अस्त्रीकरण

पाकिस्तान के फौजी विस्तार तथा इसके फौजी तानाशाह को आणविक (एटामिक) हथियारों के विकास के लिए हौसला बढ़ाने में भारत को डराने तथा वशीभूत करने की कोशिशें दीखती हैं। अमरीकी युद्ध साजिश भारतीय स्वतंत्रता पर सीधे-साधे असर डालती है और यह इसके लिए लगातार खतरे का स्रोत है। इस नीति को आगे बढ़ाते हुए रीगन ने अन्य देशों में राजनीतिक पार्टियों को, उन पार्टियों को जो अमरीकी नीतियों का पालन करती हैं, आर्थिक सहायता देने के अपने इरादे की अब घोषणा की है।

मजदूर वर्ग के कार्य

सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध शुरू करना दुनिया के श्रम आंदोलन के और सभी देशों की स्वतंत्रता के खिलाफ युद्ध की शुरूवात होगी। यदि इसे भुला दिया जाता है और अमरीकी युद्ध स जिश को शिकस्त देने की फौरी जरूरत को महसूस नहीं किया जाता है तो किसी को सर्वहारा की अंतर्राष्ट्रीय सेना का सम्मानजनक सदस्य नहीं कहा जा सकता।

बाकी दुनिया की तरह, भारतीय मजदूर वर्ग का कार्य है लाखों-लाख लोगों को लामबंद करके इस कोशिश को धराशायी करना, इस हमले को शिकस्त देना। केवल अपने दोस्त व दुश्मन की पहचान करने के द्वारा ही और दुश्मन को बेनकाब करने पर केंद्रित होकर ही हम वास्तव में अपने प्रतिरोध को बाकी दुनिया के साथ एकजुट कर सकते हैं।

भयंकर बरबादी

युद्ध का दूसरा चरित्र यह है कि यदि इसे रोका नहीं गया तो, इससे न केवल बेमिसाल बरबादी और कष्ट होंगे, बल्कि यह समूचे विश्व को भी नष्ट कर सकता है। विनाश के अभूतपूर्व हथियारों के साथ युद्ध में कोई भी विजय या पराजित नहीं होगा। आम आदमी की पराजय व बरबादी होगी।

यह इसलिए है क्योंकि अमरीकी साम्राज्यवाद ने विश्व प्रभुता व समाजवाद की बरबादी के अपने पगले इरादे के लिए अपनी सारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा विनाशकारी हथियारों के निर्माण में लगा दी है।

अमरीकी साम्राज्यावादियों द्वारा १९४५ में जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए अणु (एटम) बम से एक ही दिन में एक लाख ४५ हजार लोग मारे गए। हर इमारत, घर व पेड़ जलकर राख हो गए और हजारों लोग घायल हो गए।

तीन दिन बाद एक और अणु बम द्वारा एक और जापानी शहर नागासाकी नष्ट कर दिया गया जिससे ७५ हजार लोग मारे गए तथा इतने ही लोग घायल हो गये।

लेकिन आज के हथियारों की, जो आज कई हजार हैं, विनाशकारी क्षमता पहले के बमों की क्षमता से सौ गुना से भी ज्यादा है। मास्को, न्यूयार्क, लंदन, पेरिस, बम्बई, कलकत्ता व दिल्ली जैसे शहरों को कुछ ही मिनटों में नष्ट किया जा सकता है और लाखों-लाख को मारा जा सकता है।

दुनिया के समाने आज यह भविष्य है। अपने स्वार्थ के गुलाम अमरीकी साम्राज्यवाद ने एक नया हथियार इजाद किया है—न्यूट्रॉन बम और रीगन ने इसके भारी मात्रा में उत्पादन की इजाजत दे दी है। न्यूट्रॉन बम संपत्ति को नष्ट नहीं करता बल्कि मानव जाति को मार डालता है। यह सबसे अधिक फायदा संपत्ति के पुजारियों व मुनाफाखोरों को पहुंचाता है जिनके लिए मानव जीवन की कोई कीमत नही लेकिन मुनाफे वाली संपत्ति को हड़पना चाहते हैं।

इन हथियारों का इस्तेमाल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मानव जाति को धमकी है। उन देशों की जनता भी, जो युद्ध में शामिल नहीं है और जो युद्ध स्थलों से सैकड़ों मील दूर रहती है मृत्यु व विनाश से बच नहीं सकती। विकिरणें व जहरीला वातावरण समूची दुनिया में प्रलय मचा देगा। इस तरह के नतीजे दूसरे युद्धों के नहीं थे हालांकि उन्होंने जनता पर भयंकर पीड़ाएं लाद दी थीं।

समूची दुनिया लामबंद करो

युद्ध के खिलाफ संघर्ष को विश्व की जनता का संघर्ष बनाने के लिए समूची दुनिया में—संग्रामी व गैरसंग्रामी—सर्वहारा व गैर-सर्वहारा—समूची जनता को लामबंद करना यह संभव बनाता है। इसीलिए इस विनाश से बचने के लिए और जंगबाजों को किनारे करने के लिए आज लाखों-लाख लोग यूरोप व अमरीका में शांति आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। युद्ध के खिलाफ आंदोलन को पहले कभी भी इतना व्यापक समर्थन नहीं मिल सका जितना इसे आज मिल रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवादी जिम्मेदार

एक बार फिर जल्दी ही होने वाले इस विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है। यह अमरीकी साम्राज्यवादी है तथा और कोई नहीं। यह अमरीका था जिसने पहला अणु बम बनाया और रक्षाहीन लोगों पर गिराया। यह अमरीका था जिसने अपने पास बम होने का इस्तेमाल करते हुए सोवियत संघ को धमकी दी।

न्यूक्लीयर पनडुब्बियों, अंतर्महाद्वीपीय बम गिराने वालों, न्यूक्लीयर शक्ति से चलने वाले वायुयान वाहकों को सबसे पहले बनाने वाला अमरीका ही था और इसने मिसाइलों को बहुमुखी युद्ध हथियारों से लैस करना शुरू कर दिया। इसने न्यूट्रान हथियारों को भारी तादात में बनाना भी शुरू किया।

सोवियत संघ द्वारा कर्त्तव्यपालन

सोवियत संघ विश्व व अपनी ही जनता के बीच अपयश हो जाता यदि वह साम्राज्यवादियों के बढ़ते इसे न्यूक्लीयर अस्त्रागार के खिलाफ अपने आपको हथियारबंद करने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाता। आज इसकी प्रतिरक्षात्मक क्षमता अमरीकी विश्व प्रभुता के समाने रुकावट और युद्ध के शक्तिशाली प्रतिरोध के रूप में खड़ी है। सोवियत संघ की ओर से न्यूक्लीयर हथियार साम्राज्यवाद के हमलों का सामना करने के लिए और समाजवादी दुनिया की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षात्मक तैयारी है।

अस्त्र दौड़ पर इस द्वारा समय-समय पर उठाए गए कदमों से यह साबित होता है। कई बार इसने न्यूक्लीयर हथियारों के इस्तेमाल के आपसी त्याग के लिए और न्यूक्लीयर हथियारों के परीक्षण

कदमों के खिलाफ प्रतिरोध में एक प्रदर्शन करना भी गवारा नहीं करती।

खम करने के लिए प्रस्ताव रखे। इसने न्यूक्लीयर हथियारोंसे मुक्त क्षेत्र स्थापित करनेका आह्वान किया। इसने उन देशों के खिलाफ, जिनके पास ये हथियार नहीं है और जो अपनी भूमि पर उनकी स्थापना की इजाजत नहीं देते, न्यूक्लीयर हथियारों को इस्तेमाल न करने के लिए समझौता करने का भी आह्वान किया। और अंत में सोवियत सरकार ने विश्व के सामने यह घोषणा की कि न्यूक्लीयर हथियारों को इस्तेमाल करने में यह सर्वप्रथम नहीं होगी। विश्व की जनता ने अमरीकी सरकार से इसके जवाबकी उम्मीदकी, लेकिन दूसरीओर इस पर जोर दिया गयाकिअमरीकापहलेन्यूक्लीयर निशाने के लाभ को छोड़ नहीं सकता। पिछली अप्रैल में अमरीकी राज्य सचिव ने यह घोषणा की कि अमरीका कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनासकता जिससे इसे न्यूक्लीयरहथियारों के पहले इस्तेमाल से दूर हटना पड़े, क्योंकि इससे परंपरागत हथियारों में सोवियत निपुणता का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देश अवसर से वंचित हो जायेंगे।

सामाजिक प्रणाली में अन्तर

दो देशों व सरकारों की इन बिल्कुल विपरीत स्थितियों का क्या कारण है। यह दो सामाजिक प्रणालियों में अन्तर है—समाजवादी व साम्राज्यवादी और इनसे जुड़े वे नियम जिनके आधार पर वे काम करते हैं।

समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करने पर आधारित और गरीबी मिटाने व संकट व बेरोजगारी से समाज को मुक्त करने में लीन समाजवादी प्रणाली को उत्पादक शक्ति के निर्माण के लिए हर प्रसाधन की जरूरत है और यह अपने प्रसाधनों को प्रतिरक्षात्मक व फौजी कार्यों की ओर तब ही मोड़ता है जब इसे इसके लिए मजबूर किया जाए। इसका आर्थिक विकास विदेशी मंडियों को लूटने पर और अन्य देशों को जीत लेने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह अपनी जनता के जीवन स्तर का विस्तार करने पर और अन्य देशों के साथ आपसी लाभदायक व्यापार संबंध विकसित करने पर निर्भर करता है। इसके लिए युद्ध व फौजी खर्च अपनी जनता की उन्नति के लिए जरूरी प्रसाधनों को दूसरी तरफ मोड़ना है।

साम्राज्यवादी देशों में जहां आर्थिक संकट व बेरोजगारी चिरकालीन हैं—आज अमरीका में एक करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार हैं—पिछड़े देशों के साथ अनुचित व्यापार करके, विश्व मंडी को हथियाकर, बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से शोषित करके और अंततः दूसरों के खिलाफ क्षेत्रीय वृद्धि करके संकट की स्थिति का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। युद्ध साम्राज्यवाद का अभिन्न साथी व जरूरत है।

इसलिए मौजूदा हालात में सोवियत संघ एक ऐसी शक्ति व देश के रूपमें सामनेआया है जो विश्व शांति के लिए कटिबद्ध है और इसलिए इसे विश्व के लाखों-लाख लोगों का समर्थन मिलता है।

सोवियत संघ का जन्म पहले साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ संघर्ष में, शांति के लिए संघर्ष में हुआ। समाजवादी राज्य के पहले फैसलों में से एक है शांति के लिए फैसला, रूस की जनता को शांति का वायदा और युद्ध से इंकार।

और जन्म से ही समाजवादी राज्य ने अपनी विदेश नीति के हिस्से के रूप में विभिन्न सामाजिक प्रणालियों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की घोषणा की है।

ये सब दो महा-शक्तियों के सिद्धांत को बेनकाब करने के लिए और उन्हें बेनकाब करने के लिए जो वार्सा संधि व आक्रामक साम्राज्यवादी नाटो गठबंधन को एक समान ठहराते हैं, मजदूर वर्ग को ताकतवर बनाते हैं।

नवंबर क्रांति—लाल सलाम

नवंबर क्रांति और सोवियत संघ के मजदूर वर्ग व जनता को लाल सलाम कहते हुए भारत के मजदूर वर्ग को ७ नवंबर को सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद करना चाहिएऔरअमरीकी साम्राज्यवाद की युद्ध साजिशों का मुकाबला करने के लिए अपना निश्चय व्यक्त करना चाहिए। सीटू यूनियनों के कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। शांति के लिए इस आंदोलन के नायक के रूप में उन्हें काम करना है। भारत के मजदूरों में इस भयंकर स्थिति के प्रति और इसके प्रति मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी की चेतना बहुत कम है। वे ट्रेड यूनियन संगठन, जो दैनिक मांगों के सवाल पर सीटू के साथ सहयोग करते हैं, युद्ध और शांति के बारे में सीटू की समझ के साथ सहमत नहीं हैं और वे इस महत्वपूर्ण संघर्ष से अपनी जनता को दूर रखते हैं। इंटक के नेतृत्व में लामबंद हिस्से को भी इसी तरह दुनिया को हिला देने वाले संघर्ष से दूर रखा जा रहा है। एक सितंबर के प्रदर्शन मुख्यतः सीटू व एटक द्वारा कुछ अन्य वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर आयोजित किये गये। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में विशाल प्रदर्शन ने राज्य में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकजुट आवाज का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली व अन्य जगहों पर ४ अक्तूबर का प्रदर्शन भी मुख्यतः वामपंथी पार्टियों व उनके नेतृत्व वाले ट्रेड यूनियन केंद्रों द्वारा ही आयोजित किया गया। इसलिए सीटू को शांति के लिए संघर्ष में भारत के समूचे मजदूर वर्ग को लामबंद करने तथा हमारे देश के लाखों-लाख को युद्ध के खिलाफ एकजुट आवाज देने के लिए तैयार करने का पूरा कार्य करना पड़ा। यूरोप और अमरीका में, समाजवादी दुनिया में या अन्य जगहों पर शांति के लिए संघर्षरत लाखों-लाख लोगों के समर्थन में यह सही कार्यवाही होगी। विश्व आंदोलन को यह आश्वासन मिले कि सीटू व हमारा मजदूर वर्ग इस सवाल को भलीभांति समझ गया है और युद्ध का मुकाबला करने के लिए तथा विश्व को न्यूक्लीयर नरसंहार से बचाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ अमरीकी साजिश की कब्र खोदने के लिए सभी शांति प्रेमियों के साथ मिलकर कूच कर रहा है। ▭

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की तैयारी

'बी पी ई मुर्दाबाद' के नारे के साथ उस प्रस्ताव का स्वागत किया गया जिसे सीटू के कोषाध्यक्ष व संसद सदस्य समर मुखर्जी ने पेश किया और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरों (बी पी ई) को खत्म करने और सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा वेतनसमझौता वार्ताओं पर फैसला करने की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल की तैयारी करने का आह्वान किया गया है। कलंकित सार्वजनिक उद्यमों के ब्यूरों को बीच में लाकर सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को खत्म करने और मजदूरों के वेतन-जाम करने की भारत सरकार की अधिनायकवादी नीति की विभिन्न नारे निंदा करते रहे। समर मुखर्जी ने सरकार की इजारेदारपरस्त, जमींदारपरस्त, बहुराष्ट्रीय-निगमपरस्त और श्रम विरोधी नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। इन नीतियों के कारण मजदूरों पर खास-तौर से सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों पर हमले बढ़ रहे हैं और निजी क्षेत्र के मालिकान को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि इन नीतियों को शिकस्त देने के लिए वे एक लगातार, एकजुट व शक्तिशाली आंदोलन का निर्माण करें।

यह प्रस्ताव राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा १२ व १३ अक्तूबर को हैदराबाद में बुलाए गए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्मेलन में भाग लेने वाले करीब ६०० प्रतिनिधियों द्वारा एकमत से अपनाया गया। इस्पात, कोयला, खाद, भेल, इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिप्रिंटर्स, शिपयार्ड, एरोनाटिक्स, दवा व रसायन, एयरलाइंस, भवन व निर्माण, सोने की खाद, तांबा, बीमा, बैंक आदि उद्योगों की करीब ३०० यूनियनों की नुमाइंदगी इन प्रतिनिधियों ने की।

सम्मेलन ने राष्ट्रीय अभियान समिति को इसकी २ नवंबर को दिल्ली में होने वाली फेडरेशनों के साथ बैठक में हड़ताल की तारीख तय करने का अधिकार दिया। प्रस्ताव में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का आह्वान किया गया कि वे संघर्ष में एकता को प्रदर्शित करने के लिये तैयारी आंदोलन के रूप में ८ नवंबर को बिल्ले लगाकर धरने, प्रदर्शन व रैलियां आयोजित करके अखिल भारतीय मांग दिवस मनाएं। यह मांग दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन बीपीई के निर्देशों के खिलाफ कोयला उद्योग में देशव्यापी हड़ताल होने वाली है। इस सम्मेलन ने समूचे मजदूर वर्ग का, काम काजी जनता के हर तबके का, केन्द्रीय व राज्य सरकार कर्मचारियों का, उनका जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, युवकों, छात्रों और कामगार महिलाओं का आह्वान किया है कि वे संघर्ष में किसानों व खेतिहर मजदूरों को लामबंद करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करें।

सम्मेलन की कार्यवाही एक अध्यक्ष-मंडल ने चलाई जिसमें आर० उमानाथ (सीटू), के० एल० महेन्द्रा (एटक), माइकल फर्नांडीस (एच एम एस), एस० सेन गुप्ता (यू टी यू सी), ए० पी० चक्रवर्ती (टी यू सी सी), एच० एन० बिसवास (बी एम एस), एस० डब्लू० ढ़ाबे (राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस) और सितेश दास (यू टी यू सी-एल एस) शामिल थे।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से एम० के० पंधे (सीटू), इंद्रजीत गुप्ता (एटक), एस० सेन गुप्ता (यू टी यू सी), ए० पी० चक्रवर्ती (टी यू सी सी), राम नरेशसिंह (बी एम एस), एस० डब्लू० ढाबे (आर एम सी), माइकल फर्नांडीस (एच एम एस), ज्ञानसिंह (यू टी यू सी-एल एस) ने मजदूरों को संबोधित किया। उन्होंने सम्मेलन की पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा की और मजदूरों पर बीपीई के निर्देशों को थोपने के सरकार के कदम को रोकने के लिए एकजुट आंदोलन करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। केंद्रीय वित्तमंत्री प्रनब मुखर्जी ने ४ मई को राज्य सभा में यह साफ-साफ कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में वेतन समझौतों के सवाल को न तो उनके प्रबंधकों पर छोड़ा जाएगा और न ही सामूहिक सौदेबाजी पर। वक्ताओं ने बताया कि सरकार के निर्देश ऐसे समय पर आए हैं जब पिछले कई सालों में मजदूरों के वास्तविक वेतन काफी कम हुए हैं। मजदूरों के वेतनों को जाम करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कोशिश करने के लिए विश्व बैंक व आई एम एफ के दबाव के सामने झुकने के कारण सरकार की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने इंटक की भूमिका की भी निंदा की जो बी पी ई के निर्देशों के खिलाफ तो बोलती है लेकिन इसके खिलाफ एकजुट आंदोलन में भाग लेने से इंकार करती है। उन्होंने मजदूरों को आगाह किया कि यदि एकजुट व जुझारू आंदोलन द्वारा मजदूर नीचे से शक्तिशाली दबाव नहीं डालते हैं तो सरकार सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को खत्म कर देगी और मजदूरों के वेतनों पर भयंकर हमले शुरू कर देगी।

विभिन्न यूनियनों के करीब ७० प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया। बहस से पता चला कि विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की समस्याएं एक सी हैं और बी पी ई के निर्देशों ने वेतन समझौतावार्ताओं में रुकावट पैदा कर दी है जिसके कारण मजदूरों को यूनियन व

उद्योग के आधार पर आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वह भी सामने आया कि करीब १५० सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में प्रबंधकों के नए वेतन समझौतों को रोक दिया है और वे बी पी ई के निर्देशों को मानने के लिए मजदूरों को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग सभी का सरकारी नीतियों व इंटक की विघटनकारी भूमिका के प्रति एक समान अनुभव था—उन्होंने एक ही मत रखा कि बी पी ई के निर्देशों को अस्वीकार किया जाए और सामूहिक सौदेबाजी व मजदूरों की मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए हड़ताली कार्यवाही सहित देश-व्यापी एकजुट आंदोलन शुरू किया जाए। वक्ताओं ने कोयला मजदूरों के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त की जो ८ नवम्बर को देश-व्यापी हड़ताली कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अध्यक्षमंडल की ओर से बहस का समापन करते हुए सीटू के आर. उमानाथ ने कहा कि सम्मेलन में बहस से तीन प्रमुख लक्ष्य उभरकर आए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मजरियों में अखिल भारतीय एकता, समझौतों की शर्तों पर एक कामन समझ, और संघर्ष में सही अर्थों में एकता। सरकार के वेतन को उत्पादकता से जोड़ने और १९८२ वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित करने के एकतरफा फैसले की उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने बंबई के कपड़ा मजदूरों की नो महीने लंबी हड़ताल का उदाहरण देते हुए इस तथाकथित घोषणा के पाखंड को बेनकाब किया और कहा कि सरकार के इंटक यूनियन थोपने के अड़ियलपन ने मजदूरों को ८०० करोड़ रुपये की उत्पादन हानि के बावजूद लंबी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्पादकता व उत्पादन में वृद्धि की बात केवल औद्योगिक मालिकान के मुनाफे बढ़ाने के लिए है। कई उद्योगों में प्रबंधक उत्पादन में कटौती करने पर तुले हुए हैं। जहां उत्पादन में कटौती मुनाफे बढ़ाती है वहां सरकार चुप रहती है और जहां उत्पादन में वृद्धि मुनाफा बढ़ाती है वहां यह चिल्लाती है। दोनों ही मामलों में मजदूर बली का बकरा बनते हैं। उन्होंने मजदूरों को सावधान किया कि वे सरकारी जोड़-तोड़ के शिकार न बनें और उनका आह्वान किया कि वे सम्मेलन में तय की गई कामन समझ को मजदूरों में निचले स्तर तक ले जाएं और सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने के लिए उनमें रुझान पैदा करें। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के साथ-साथ वैकल्पिक आर्थिक नीति का रास्ता भी बताया जाए—एक बार यह रास्ता जनता की समझ में आ जाएगा तो यह सरकार की नीतियों को बदलने के लिए एक शक्तिशाली ताकत बनेगी।

सम्मेलन में बंबई के कपड़ा मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करते हुए और बिहार प्रेस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव अपनाए गए।

सम्मेलन के बाद सचिवालय के समीप एक जनसभा आयोजित की गई जिसमें कई हजार मजदूरों ने भाग लिया। रैली को संबोधित करने वालों में समर मुखर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, राम नरेशसिंह, एस डब्लू ढाबे व अन्य शामिल थे।

प्रस्ताव

हैदराबाद में १२-१३ अक्तूबर को संपन्न सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की यूनियनों का अखिल भारतीय सम्मेलन समूचे देश के मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर बढ़ते हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। भारत सरकार विभिन्न कानूनों के जरिए मजदूरों के संगठित होने के अधिकार तथा संगठन बनाने की आजादी में सुनियोजित तरीके से कटौती करती जा रही है जबकि तमाम मजदूरों पर वेतन जाम की आम नीति थोपने के प्रयास जारी हैं। मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी तथा हड़ताल के अधिकार की उपेक्षा की जा रही है तथा उन्हें गुप्त मतदान की लोकतांत्रिक पद्धति के जरिए यूनियनों की मान्यता के जायज अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। एक स्थिति में जबकि मुद्रा स्फीति और मंहगाई के कारण मजदूर वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, औद्योगिक संबंधों में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही है।

बंबई में ४ जून १९८१ को संपन्न सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय सम्मेलन सरकार की इजारेदारपरस्त, बहुराष्ट्रीय निगमपरस्त और जमींदारपरस्त नीतियों का खुलासा पेश किया जो मजदूर वर्ग और देश की गरीब जनता के जीवन को दुश्वार बनाती जा रही हैं तथा उन नीतियों के खिलाफ लंबे संघर्ष की जरूरत को रेखांकित किया था। २३ नवम्बर १९८१ को संसद पर प्रदर्शन और १९ जनवरी १९८२ को एक दिन की हड़ताल सरकार की नीतियों के प्रति अपने विरोध का हजहार करने की दृढ़ संकल्पी कोशिशें थीं। इन कार्यवाहियों के दौरान मजदूर वर्ग ने किसानों को फसलों के लाभकारी दाम तथा खेतिहर मजदूरों को बेहतर मजदूरों का सवाल भी उठाया।

क्योंकि भारत सरकार ने नए श्रम कानूनों के बारे में ट्रेड यूनियनों से सलाह-मशविरा करने से इंकार कर दिया था इसलिए राष्ट्रीय अभियान समिति को १७-१८ सितंबर को संपन्न राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन का बहिष्कार करना पड़ा। इससे भी गंभीर बात यह है कि आई एम एफ की शर्तों के चलते भारत सरकार मजदूरों के संघर्षों को कुचलने के मामले में ज्यादा क्रूर होती जा रही है। कई मामलों में तो मानव श्रम बचाने वाली तकनीकी प्रक्रिया के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटाने तक की धमकी दी जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उन मजदूरों और कर्मचारियों को हमले का खास निशाना बनाया जा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत बनाए जाने की हिमायत करते हैं। अफसरशाही तौर-तरीकों से इन प्रतिष्ठानों का प्रशासन चलाने और गलत आर्थिक नीतियों के कारण ये प्रतिष्ठान भारी घाटे में चल रहे हैं और भ्रष्टाचार व घूसखोरी इनके धन को बरबाद कर रही है। भारत में पहले से ही उत्पादित होने वाले उत्पादनों के और उपकरण के आयात, देश की तकनीकी क्षमता के उपयोग और उसके विकास में असफलता तथा प्रमुख परियोजनाओं के सिलसिले में विदेशी सह-

[illegible] ज्यादा निर्भरता के परिणाम-स्वरूप आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को भारी नुकसान पहुंच रहा है सरकारी नीतियों में जारी धांधलियों का सारा बोझ मजदूरों पर डाला जा रहा है जिन्हें यह बेतुकी दलील देकर कि वे 'उच्च वेतन के टापू' है, इन प्रतिष्ठानों में जायज अधिकार देने तक से इंकार किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में ठेका मजदूरों की स्थिति तो और भी दर्दनाक है जबकि निर्मम ठेकेदारों तथा भ्रष्ट अफसरों के समान स्वार्थों के कारण ठेका मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहां तक कि प्रतिष्ठापूर्ण एशियाड प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के जरिए लगाए गए मजदूरों तक को कानूनन देय न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं नहीं जा रही है जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोयला खानों में माफिया गिरोहों ने प्रशासन व पुलिस की पूरी-पूरी मदद से आतंक राज कायम कर रखा है। सम्मेलन यह नोट करता है कि सरकार ने ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (बी पी ई) के जरिए जो एक तरफा निर्देश थोप दिए हैं, अनेक प्रतिष्ठानों में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। इन निर्देशों के अनुसार वेतन बढ़ोत्तरी को उत्पादकता में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी के साथ जोड़ना होगा। और कोई भी वेतन समझौता पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि यदि पुराना समझौता समाप्त होने से पहले ही नए समझौते पर दस्तखत नहीं हुए तो मजदूरों को एरियर भी नहीं मिलेंगे। ये निर्देश फिर यह सीमा लगाते हैं कि वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ाने वाला आय-व्यय मौजूदा वेतन बिल के १० प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस पर भी बल दिया गया है कि वर्ष १९६० के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति प्वाइंट वृद्धि पर एक रुपया ३० पैसे के मंहगाई भत्ते के फार्मूले के साथ किसी भी सूरत में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश यह भी कहते हैं कि समझौता चार साल की अवधि के लिए होना चाहिए।

वास्तव में इन निर्देशों का असली मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में होने वाले वेतन समझौतों में जबरदस्त दखलंदाजी है है और यदि इनको पूरी तरह लागू कर दिया जाता है तो इन प्रतिष्ठानों में सामूहिक सोदे के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह पाएगी।

इन्हीं निर्देशों के कारण स्टील, इंडियन आयल और भेल में वेतनवार्ताओं में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। बंगलौर व हैदराबाद स्थित उद्योगों में जैसे आई टी आई, एच एम टी, एच ए एल, बी ई एम एल, बी ई एल, ई सी आई एल, मिधानी, बी डी एल तथा उर्वरक आदि उद्योगों के पिछले वेतन समझौते ३१ दिसंबर १९८२ को समाप्त हो रहे हैं, लेकिन नयी वेतन वार्ता अभी भी ढंग से शुरू नहीं हो सकी है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०, नेय वेली लिगनाइट कार्पोरेशन, मेकोन तथा अन्य प्रतिष्ठानों में प्रबंधकों ने बी पी ई द्वारा मंजूर प्रस्ताव से ज्यादा देने से इंकार कर दिया है जिससे समझौतों में रुकावट पैदा हो चुकी है। कोयला उद्योग में भी वेतनवार्ता में रुकावट आ चुकी है क्योंकि एक तो सरकार ने इंटक का पक्ष लेकर संयुक्त द्विपक्षीय कमेटी के पुनर्गठन का एकतरफा फैसला लिया है और दूसरे इस उद्योग में पिछले समझौते तक को लागू नहीं किया गया है। मौजूदा अधिकारों को छीनते हुए और हस्ताक्षरित समझौतों से मुकरते हुए भारत सरकार ने जीवन बीमा तथा आम बीमा कर्मचारियों का सामूहिक सौदे का अधिकार कानूनन छीन लिया है।

जिन प्रतिष्ठानों के मजदूरों को एक रुपया ३० पैसे प्रति प्वाइंट की दर से ज्यादा मंहगाई भत्ता मिल रहा है उनसे कहा जा रहा है कि वे जब तक मंहगाई भत्ते की दर एक रुपया ३० पैसे मात्र स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकती। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में प्रबंधक और यूनियनें पेंशन योजना को अंतिम रूप दे चुकी हैं। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद बी पी ई ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी है। एच एम सी एल के प्रबंधकों ने एक अंतरिम सहायता देना स्वीकार करने के बाद अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान मनमाने तरीके से स्थगित कर दिया और जब मजदूरों ने अतिरिक्त भत्ते के लिए अभियान चलाया तो अंतरिम सहायता की अदायगी रोककर अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान कर दिया।

आज के हालात में मंहगाई भत्ते की दर १ रु० ३० पै० स्थिर कर देने के निर्देश का मतलब है यूनियनों द्वारा समझौते पर दस्तखत कर दिए जाने के बाद भी वेतन में कटौती जब तक ये निर्देश वापस नहीं ले लिए जाते और मंहगाई की पूरी भरपाई नहीं दी जाती तब तक आगे होने वाले तमाम वेतन समझौते वेतन में कटौती के शिकार होते रहेंगे।

इस तरह सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में वेतन वार्ताओं के दौरान बी पी ई द्वारा पर्दे के पीछे से दिए जाने वाले हुक्म के चलते द्विपक्षीय मंचों को भारी नुकसान पहुंचा है और इन मंचों के कुचले जाने का गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

इसलिए, ट्रेड यूनियनों की यह मांग एकदम जायज है कि यदि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सामूहिक सौदे को बराबर रखना है तो ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज को खत्म किया जाए और वेतनवार्ताओं में इसकी मनमानी दखलंदाजी पर रोक लगायी जाए।

सम्मेलन संतोष के साथ यह नोट करता है कि कोयला, स्टील व भेल उद्योगों में सफलतापूर्वक सम्मेलन आयोजित किए गए जिनमें आंदोलनों के संयुक्त कार्यक्रम तय किए गए। बी पी ई के विरुद्ध केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के अभियान के परिणाम-स्वरूप इंटकी नेता भी बी पी ई के निर्देशों का विरोध करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन उन्होंने इन निर्देशों के खिलाफ किसी संयुक्त आंदोलन में शामिल होने से साफ इंकार कर दिया है।

यह सम्मेलन भारत सरकार की वेतन नीति की कड़ी निंदा करता है जिसे कि वह बी पी ई के जरिए मनमाने तरीके से लागू करने पर आमादा है। सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम यूनियनों का आह्वान करता है कि वे ऐसे किसी भी समझौते पर दस्तखत न करें जिसमें १ रु ३० पै० मंहगाई भत्ता दर समेत बी पी ई का कोई भी निर्देश थोपने की कोशिश की जाए। सम्मेलन देश के मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वे हर वेतनवार्ता के दौरान कदम-कदम पर इन निर्देशों के खिलाफ संघर्ष करें और इनके खिलाफ संयुक्त आंदोलन की तैयारी करें ताकि सरकार को इन्हें वापस लेने के

(शेष पृष्ठ २४ पर)

कोयला मजदूरों की ८ नवम्बर को हड़ताल को सफल बनाओ

सीटू के सेक्रेटेरियट की एक बैठक २० अक्तूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बी. टी. रणदिवे ने इसकी अध्यक्षता की।

एम. के. पंधे ने कोयला मजदूरों की ८ नवंबर को होने वाली हड़ताल के लिए अभियान को तेज करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दी। अब तक सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेलनों में काफी मात्रा में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुछ और क्षेत्रीय सम्मेलनों के कार्यक्रम तयार किए गए हैं जिनमें समर मुखर्जी व मुहम्मद इस्माइल भाग लेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के बाद सेक्रेटेरियट ने कोयला उद्योग में सभी सीटू यनियनों का आह्वान किया है कि वे ८ नवंबर को हड़ताल की महान सफलता के लिए तहेदिल से काम करें।

हिसाब-किताब (एकाउंट्स) की प्रणाली पर, जिस पर बंगलौर में संपन्न वर्किंग कमेटी की पिछली बैठक में भी विचार किया गया था, विचार किया गया। टी.एन.नंबीराजन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर यह महसूस किया गया कि हिसाब-किताब की अच्छी जानकारी रखने वाले कुशल स्टाफ के बिना दोहरी-प्रविष्टी प्रणाली शुरू करना शायद संभव न हो। जनवरी १९८३ से नई प्रणाली शुरू करने की कोशिशें की जाएंगी। इसके शुरू होने तक ३१ दिसम्बर १९८१ तक का हिसाब-किताब तैयार किया जाना चाहिए और आडिट कराया जाना चाहिए।

कठिन हालात में सम्पन्न सीटू के राजस्थान राज्य सम्मेलन पर नृसिंह चक्रवर्ती ने रिपोर्ट दी। राज्य के हर कोने से प्रतिनिधियों की भागीदारी के नजरिये से यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। सम्मेलन की मेहमानवाजी करने वाले कोटा के मजदूरों का उत्साह प्रशंसनीय था। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार भड़काने की कार्यवाहियां हो रही हैं और किस प्रकार नए नेतृत्व को हत्या के मामले में फंसाकर उन्हें आतंकित करने की कोशिशें की जा रही हैं। कई केंद्रों में दमन शुरू कर दिया गया है। संगठन को और मजबूत करने के लिए २३-२४ अक्तूबर को जयपुर जिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें नृसिंह चक्रर्ती व सुशील भट्टाचार्य, संसद, भाग लेंगे। बी. टी. रणदिवे ने इस विषय में और भी बातें बताई और बताया कि नया नेतृत्व किस प्रकार एकमत से चुना गया।

सेक्रेटेरियट ने फिर सीटू के पांचवें सम्मेलन के सवाल पर विचार किया और इसे कानपुर में आयोजित करने का फैसला किया। नृसिंह चक्रवर्ती ने सीटू की उत्तर प्रदेश कमेटी द्वारा चन्दा इकट्ठा करने और सम्मेलन को आयोजित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कानपुर में सीटू की जिला कमेटी चुनने के लिए सभी यूनियनों का एक सम्मेलन ३१ अक्तूबर को संपन्न होगा और इसमें सम्मेलन के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि वे इसमें भाग लेंगे फिर भी उन्होंने निवेदन किया कि समर मुखर्जी भी इसमें हाजिर रहें। सेक्रेटेरियट ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सम्मेलन की तारीखें, जो २ से १७ अप्रैल १९८३ के बीच होनी चाहिए, ३० अक्तूबर को तय की जाएंगी जब उत्तर-प्रदेश सीटू के अध्यक्ष व महासचिव दिल्ली में मौजूद होंगे।

यह नोट किया गया कि क्योंकि हर राज्य से प्रतिनिधियों की संख्या तय की जानी है इसलिए उस सदस्यता की संख्या महत्वपूर्ण है जिसके लिए चंदा प्राप्त हो चुका है। अनेक यूनियनों ने अभी तक १९८१ तक का संबद्धता चंदा नहीं दिया है। इसलिए सही संख्या प्राप्त करने के लिए दिसंबर १९८२ तक एक नोटिस १९८१ तक के संबद्धता चंदे की अदायगी के लिए जारी किया जाएगा।

इस विचार विमर्श के बाद यह महसूस किया गया कि दिसंबर १९८२ से पहले सीटू की जनरल काउंसिल की एक बैठक बुलाई जाए।

एम. के. पंधे ने हैदराबाद में सम्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्मेलन के बारे में बताया। सीटू यूनियनों की भागीदारी आमतौर पर अच्छी थी। उन्होंने बताया कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की हड़ताल की तारीख पर विचार करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय अभियान समिति यह महसूस करती है कि अब समय आ गया है जब बम्बई की तरह एक और अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जनरल काउंसिल की बैठक सम्मेलन के साथ-साथ आयोजित की जाए ताकि हमारे साथी पूरी तरह दोनों में भाग ले सकें। सेक्रेटेरियट ने फैसला लिया कि दोनों को एक ही साथ पर आयोजित करने की संभावनाओं को देखा जाए।

कामरेड मुकुंद मंडल

जब बैठक चल रही थी तब कामरेड मुकुंद मण्डल, सांसद, सी· पी. आई. (एम) जिनका इलाज ए आई आई एम एस में हो रहा था की असामयिक मृत्यु की खबर पहुंची। एक मिनट तक मौन खड़ होकर इस कामरेड की याद में सेक्रेटेरियट ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

इसके बाद बैठक खत्म होने की घोषणा कर दी गई। ▭

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)
पी. राममूर्ति
मनोरंजन राय
नीरेन घोष
सुधीन कुमार
एम. के. पंधे (सम्पादक)

कोयला हड़ताल के लिए पूर्ण तैयारी

देश भर के ७ लाख कोयला मजदूर १९७९ के वेतन समझौते को लागू करने, विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश किए गए मांगपत्र पर शीघ्र समझौता करने तथा बी. पी. ई. के निर्देशों एवं जे. बी. सी. सी. आई. के मनमाना पुनर्गठन के खिलाफ ८ नवम्बर को एक दिन की हड़ताल करने के लिए तैयार हैं।

ईस्टर्न व वेस्टर्न कोलफील्ड्स में सम्मेलन हो चुके हैं और १८ अक्तूबर को प्रबंधकों व सी. आई. एल. मुख्यालय को हड़ताली नोटिस दे दिए गए हैं।

इस बीच कोयला यूनियनों की अखिल भारतीय संघर्ष समिति की जिसमें सीटू, एटक, यूटीयूसी, एच.एम.एस, बी.एम.एस. व आर. एम. सी. (दारा) शामिल हैं बैठक ५ अक्तूबर को दिल्ली में सम्पन्न हुई और प्रशासन के समक्ष पेश करने के लिए मांग पत्र तैयार किया गया।

संघर्ष समिति के नेताओं ने ७ अक्तूबर को दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में १९८१ से कोयला उद्योग के लिए जे.बी.सी. सी. आई. की बैठक बुलाने से इन्कार करने के लिए सी. आई. एल. के प्रबंधकों तथा सरकार की कड़ी निन्दा की। इसके कारण पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधाओं, गृह निर्माण तथा ठेका मजदूरी के खात्मे आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मौजूदा कमेटी को भंग करके मनमाने तथा अलोकतांत्रिक तरीके से जे. बी. सी. सी. आई० का पुनर्गठन करने के कारण केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा पेश की गई मांगों पर वार्ता में रुकावट पैदा हो गई है। सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ इंटक यूनियन को अपने राजनीतिक संरक्षण का पर्दाफाश करते हुए नई कमेटी में इसकी संख्या को पिछली दो से चार कर दिया है तथा एक सीट अस्तित्वहीन कुलकर्णी ग्रुप को भी दी है जो एच० एम० एस० के नाम से चल रहा है और एकजुट आंदोलन में तोड़-फोड़ करने की कोशिश करते हुए सरकार की आवाज में अपनी आवाज मिला रहा है। बी० एम० एस० को, जो पिछली जे०बी०सी०सी०आई० का घटक था तथा पिछले वेतन समझौते में शामिल था, एकतरफा तौर पर बिना कोई कारण बताए कमेटी से अलग कर दिया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में सीटू, एटक और एच. एम० एस० के समक्ष थोपी गई कमेटी का बहिष्कार करने के सिवाए और कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने बी० एम० एस० तथा आर० एम० सी० (दारा)—के साथ मिल कर कोयला मजदूरों की जायज मांगों को हासिल करने के लिए देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया।

बी.पी.ई. के निर्देशों की निन्दा करते हुए संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि ये निर्देश मजदूरों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को खत्म करते तथा उनके वेतन जाम करते हैं। विदेशों में कोयला मजदूर सबसे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं परन्तु भारत में उन्हें सबसे नीचे के स्तर पर रखा गया है। बढ़ती हुई खदान दुर्घटनाएं उनकी दुर्दशा का संकेत मात्र हैं। कोयला मजदूरों की मांगें जन-संघर्षों के माध्यम से बी. पी. ई. के निर्देशों को पराजित करके ही हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि ८ नवम्बर की हड़ताल तो एक चेतावनी तथा भावी दीर्घकालीन संघर्षों की पूर्व सूचना मात्र है। ▭

रैनबेक्सी के मजदूरों की पूर्ण हड़ताल

दिल्ली में ओखला और नेहरू प्लेस में स्थित रैनबेक्सी लेबोरेट्रीज लि. के लगभग १००० मजदूरों ने प्रबंधकों की दमनात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ ११ अक्तूबर को एक दिन की पूर्ण हड़ताल की।

रैनबेक्सी कामगार यूनियन के पुराने नेतृत्व ने प्रबंधकों की दलाली करते हुए उत्पादकता से जुड़े वेतन सहित प्रबंधकों की तमाम बातों को स्वीकार करते हुए मजदूरों की पीठ पीछे एक समझौता किया था। मजदूरों ने इस समझौते को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया तथा गुप्त मतदान के द्वारा पुराने नेतृत्व को भी हटाकर यूनियन को सीटू के साथ संबद्ध करा लिया। प्रबंधक ने तुरन्त गुस्से में आकर यूनियन के नये महासचिव दीपक बागची को पांच अन्य लोगों के साथ निलम्बित कर दिया। इसके बाद प्रबंधकों ने कई कार्यकर्त्ताओं को चार्जशीटें दीं तथा लगभग १०० कर्मचारियों को चेतावनी पत्र दिये। प्रबंधकों को इससे संतोष नहीं हुआ और उन्होंने महिलाओं सहित तमाम मजदूरों को धमकाने, उनके साथ झगड़ा करने तथा उन्हें भयभीत करने के लिए असामाजिक तत्वों को लगाया। यूनियन द्वारा बार-बार ज्ञापन देने के बाद उप श्रमायुक्त ने ८ अक्तूबर को एक बैठक बुलायी परन्तु प्रबंधकों ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया। मजदूर हड़ताल का नोटिस देने के लिए मजबूर थे। प्रबंधकों ने हड़ताल को तोड़ने के लिए ५० से ६० स्थानीय ठगों को भाड़े पर लिया। परन्तु मजदूरों की एकजुट ताकत के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के महासचिव, संसद सदस्य सुशील भट्टाचार्य ने सफल हड़ताल के लिए मजदूरों को बधाई दी।

यूनियन ने प्रबंधकों को एक नया मांग पत्र दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी जारी है। ▭

बैंक कर्मचारियों ने फेडरेशन बनाई

वर्ग संघर्ष की नीति अपनाने, प्रबन्धकों की दमनकारी नीतियों तथा सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रतिज्ञा के साथ कलकत्ता में १४-१५ अक्तूबर को संपन्न एक सम्मेलन में बैंक एंप्लाईज फेडरेशन आफ इंडिया का गठन किया गया। सम्मेलन में १५ राज्यों से ७६००० कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ५०५ प्रतिनिधियों तथा आब्जर्वरों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन से पूर्व १३ अक्तूबर को सुबोध मल्लिक सक्वायर में रैली से पहले जुलूस का आयोजन किया गया जिसमें १५००० लोगों ने हिस्सा लिया।

स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉ० अशोक मित्रा ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि बी० ई० एफ० आई० का गठन प्रबंधकों तथा पुराने वर्ग सहयोगवादी नेतृत्व की साजिशों का जुझारू जवाब देने के लिए किया गया है।

सी पी आई (एम) के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सरकार की जन-विरोधी तथा इजारेदार, भूस्वामी, और बहुराष्ट्रीय कंपनी समर्थक नीतियों के खिलाफ मजदूर वर्ग के सभी तबकों के एकजुट संघर्षों की गम्भीर जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों ने देश के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा नैतिक ढांचे को व्यवस्थित रूप से बरबाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एन० एस० ए०, एस्मा तथा अन्य बहुत से दमनकारी कानून पनप रहे जनसाधारण के विद्रोह को दबाने के लिए ही बनाए गये हैं। अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में होने के कारण संगठित बैंक कर्मचारियों को इन नीतियों में परिवर्तन के लिए दीर्घकालीन संघर्ष छेड़ने के लिए अन्य मजदूर वर्गों के साथ अपनी यथोचित भूमिका अदा करनी है।

सीटू उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे बैंक कर्मचारियों के आंदोलनों की गतिविधियों से तथा उनकी मांगों से अच्छी तरह परिचित हैं और वे यह भी अच्छी तरह से समझते हैं कि किन परिस्थितियों में नया संगठन कायम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, नीतियों को तय करने के मामले में साधारण सदस्यों की हिस्सेदारी, न कि कुछ नेताओं द्वारा सभी मामलों में गुप्त रूप से निर्णय लेना, आदि ट्रेड यूनियन आंदोलन के मजबूत आधार हैं। जब इन तौर-तरीकों को बहाल करने के सभी प्रयास असफल जाते हैं तथा किसी संगठन के नेता भिन्न विचार रखने वालों को निकाल बाहर कर देते हैं तो दूसरा संगठन कायम करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं रह जाता। बी० ई० एफ० आई० भी वर्षों के ऐसे ही अनुभवों के कारण अस्तित्व में आया है। इस नये संगठन को ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिएं। विचारों में मतभेद हो सकते हैं, परन्तु एकजुट संघर्ष के लिए एक राय पर पहुंचने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

एक सरकार के मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों के हड़ताल के अधिकार को आवश्यक रूप से हमेशा बरकरार रखना चाहिए और उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

ज्योति बसु ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ किये जा रहे शरारतपूर्ण प्रचार का प्रतिवाद करने की गम्भीर जरूरत का जिक्र किया। बैंक कर्मचारियों को अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हुए जनसेवा को अपना कर्त्तव्य समझना चाहिए। अपनी जायज मांगों तथा न्यायोचित संघर्ष के लिए जनसमर्थन जुटाने की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है। छोटे किसानों तथा भूमिहीनों की हालत को सुधारने के लिए वाम मोर्चा सरकार के प्रयासों की तरफ बैंक कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि मात्र भूमि उपलब्ध कराने से कुछ नहीं होगा कि जब तक कि उन्हें खेती करने के लिए जरूरी आर्थिक मदद न उपलब्ध कराई जाय। बैंकरों से संपर्क किया जा चुका है परन्तु वे अपेक्षा करते हैं कि इस संदर्भ में स्वयं बैंक कर्मचारीगण उन्हें अपना पक्का साथी बनाने के लिए समाज के गरीब हिस्सों, किसानों, भूमिहीन मजदूरों, बेरोजगारों, तथा अशिक्षितों को बैंक से कर्ज उपलब्ध कराने में सीधे प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांगों का समर्थन करने की अपनी नीति के तहत वाम मोर्चा सरकार ने बोनस तथा अन्य मांगों से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए पहल की है। जब भी मजदूर वर्ग का कोई जोरदार आंदोलन होता है तो केन्द्र सरकार चाहती है कि वाम मोर्चा सरकार उसके खिलाफ पुलिस का प्रयोग करे। परन्तु वाम मोर्चा सरकार ऐसा करने से साफ-साफ इंकार करती है क्योंकि जनवादी आंदोलनों को दबाना हमारी नीति नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक एंप्लाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया मजदूर वर्ग के सिद्धान्तों तथा तदनुरूप कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़े।

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री तथा फेडरेशन ऑफ मेटल एण्ड इंजीनियरिंग वर्कर्स के महासचिव शान्ति घटक, ऑल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन की अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी सहगल, ए० आई० ई० ई० ए० के शान्ति भट्टाचार्य, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नेता सिसिर भट्टाचार्य, १२ जुलाई कमेटी के भाबातोष राय तथा मर्केन्टाइल एंप्लाईज फेडरेशन के के० पी० केडिया तथा अन्य लोगों ने सम्मेलन का अभिनन्दन किया।

मांगें :—सम्मेलन ने एक मांगपत्र भी तैयार किया जिसमें सेवा-शर्तों सहित अन्य संबंधित मांगों के अतिरिक्त रहन-सहन के

(शेष पृष्ठ ३१ पर)

ठेका मजदूरों के लिए समर मुखर्जी का विधेयक

ठेका मजदूरों की सेवा व कार्य-शर्तों के सवाल पर सीटू की जनरल काउंसिल की सितम्बर १९८० व अगस्त १९८१ की दो बैठकों में विचार किया गया था। लोकसभा में सी० पी० आई० (एम०) के सांसद और सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य एम० एम० लारेंस ने एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर २६ फरवरी १९८२ को बहस की गई। एकमत से यह पाया गया कि मौजूदा ठेका मजदूर (नियमन व समापन) कानून में खामियां मौजूदा स्थिति के लिये जिम्मेदार हैं।

समर मुखर्जी, सांसद व कोषाध्यक्ष, सीटू ने इस कानून में संशोधन के लिए १३ जुलाई १९८२ को एक निजी सदस्य का विधेयक वितरित किया। इस विधेयक को ६ अक्तूबर को लोकसभा में पेश किया गया और उन्होंने इसके लक्ष्य के बयान में कहा कि :

'मौजूदा विधेयक इन खामियों को दूर करने तथा ग्रामीण असंगठित श्रम से आने वाले ठेका मजदूरों को, यानी हमारे समाज के सबसे गरीब व कमजोर तबकों को जिनका शोषण न केवल निर्मम ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है बल्कि तथाकथित पढ़ेलिखे प्रबंधकों द्वारा भी किया जा रहा है जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम शामिल हैं जो लगातार व स्थाई प्रकृति के ज्यादा से ज्यादा काम को ठेके परदे रहें, हैं संरक्षण देने के इरादे से पेश किया गया है।

कानून के तहत निर्तिलसलाहकार बोर्डों की कार्यप्रणाली के रास्ते में इस कानून की खामियां आड़े आई हैं जैसा कि ठेका श्रम के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाने वाली अधिसूचना जारी करने के कई फैसले जो दिसम्बर १९७७ में लिये गये थे अभी तक सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं। यह विधेयक इन खामियों को भी दूर करता है।

कानून में इसे लागू करने के लिए किसी भी मशीनरी का प्रावधान नहीं है और कानूनों के उल्लंघन तथा उन्हें सुविधाओं से वंचित रखने के खिलाफ न्याय पाने का कोई अवसर मजदूरों के पास नहीं था सिवाए इसके कि वे औद्योगिक विवाद खड़ा करें। विधेयक में मजदूरों को ऐसे अवसर दिए गए हैं ताकि वेतन आदि के सवाल को तय किया जा सके। कानून के तहत यह संरक्षण देश में श्रम ताकत के सबसे कमजोर तबके के अमानवीय शोषण को खत्म करेगा"

वेतन का सवाल

मौजूदा कानून में सबसे बड़ी खामी ठेका मजदूरों के वेतनों के बारे में है। हालांकि कानून के तहत बनाए गए नियमों की धारा २५ (२)(५)(ए) में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां ठेका मजदूर मूल मालिक द्वारा सीधे भर्ती किए गए मजदूरों की तरह का समान काम करते हैं तो उनके वेतन दर, छुट्टियां, कार्य के घंटे और अन्य सेवाशर्तें भी समान होंगी, लेकिन वह स्वयं कानून में शामिल नहीं है। अब इस बात को मूल कानून में इन साफ शब्दों में जोड़कर यह खामी दूर की जा रही है :

"ठेका मजदूरों को वेतन देने की अंतिम जिम्मेदारी मूल मालिक पर होगी की शर्त के साथ, ठेकेदारों की उन द्वारा ठेका मजदूर के रूप में भर्ती किए गए हर मजदूर को वेतनों की अदायगी की जिम्मेदारी होगी और यह अदायगी होगी न्यूनतम वेतन कानून, १९४८ के तहत निर्धारित वेतन के समान या उद्योग में या मूल मालिक के प्रतिष्ठान में मौजूदा वेतन के समान या औद्योगिक विवाद कानून, १९४७ के तहत पंजीकृत समझौते में मजदूरों द्वारा सहमत वेतन के समान, इनमें से जो भी सबसे ज्यादा हो और यह अदायगी वेतन का भुगतान कानून, १९३६ के तहत बताई गई अवधि के खत्म होने के पहले की जाएगी।"

समर मुखर्जी ने मूल कानून में जोड़ने के लिए कई नई धाराएं भी प्रस्तावित की हैं। ये नई धाराएं ठेका मजदूरों को ओवर टाइम, बोनस की अदायगी, कार्य के घंटे, महिला मजदूरों के लिए प्रसूति छुट्टी, ई० एस० आई० सुविधाओं, प्रोविडेंट फंड, स्थायीकरण और अन्य लाभों से सम्बंधित हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पी० एन० भगवती व बहरुल इस्लाम ने १८ सिम्बर १९८२ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम वेतन कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन देना और ठेका मजदूर कानून के तहत प्राप्त सुविधाओं से वंचित रखना जबरन मजदूरी के समान है जिस पर संविधान के अनुच्छेद २३ के अनुसार प्रतिबन्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून का उल्लंघन करने पर ठेकेदारों पर किए जाने वाले जुर्माने इतने कम हैं कि कानून को लागू न करना ही उन के लिए लाभदायक है। ठेकेदारों को सख्त सजाएं देने का और उसे लागू करने की पूरी जिम्मेदारी मूल मालिक पर सौंपने का प्रावधान करके विधेयक द्वारा इस खामी को भी खत्म किया जा रहा है।

ठेका श्रम पर स्थाई कमेटी में सीटू के प्रतिनिधि जगजीत सिंह लायलपुरी इस मामले को कमेटी की २३ अक्तूबर की बैठक में उठाने वाले हैं। ▭

इस्पात वेतन बातचीत अभी कामयाब नहीं

इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय ज्वाइंट कमेटी की कई बैठकों के बावजूद नए वेतन समझौते के लिए वार्ता में प्रगति कछुए की चाल से हो रही है जिसके कारण ट्रेड यूनियनों द्वारा अपने मांगपत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से ज्यादातर पर अभी कोई समझौता नहीं हो सका है। फिर भी सेल (एस ए आई एल) प्रबंधक यहप्रभाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मांग पत्र पर बस समझौता होने ही वाला है।

प्रबंधकों ने अब तक केवल निम्न ही स्वीकार किया है :

१. न्यूनतम वेतन ४०० रुपये की बजाए ५५० रुपये निर्धारित किया गया है। इसका केवल यह मतलब है कि १५० रुपए का मंहगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया गया है। प्रबंधक मौजूदा ८ रुपये की वार्षिक वृद्धि की न्यूनतम दर को बढ़ा कर ११ रुपये करना मान गए हैं। वार्षिक वृद्धि की अधिकतम दर ५५ रुपये कर दी जायेगी।

२. स्कूटर या मोटरसाइकल खरीदने के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए वेतन सीमा हटा ली गई है और सभी मजदूर अब इस तरह की अग्रिम राशि प्राप्त कर सकेंगे। जिन मजदूरों के पास स्कूटर या मोटरसाइकल है उन्हें ७५ रुपये मासिक की बजाए १०० रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। जिन मजदूरों के पास मोपेड (छोटी-मोटरसाइकल) है उन्हें मौजूदा ४० रुपये की बजाय ५५ रुपये महीना भत्ता मिलेगा।

३. जो मजदूर कम्पनी की ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट खर्च के रूप में १ रुपये ६० पैसे की प्रतिदिन की हाजरी की दर से विशेष भत्ता दिया जाएगा। एक महीने में ऐसे भत्ते की न्यूनतम राशि मौजूदा २० रुपये ही होगी।

४. मजदूरों को मकान किराया भत्ता १९७० के वेतनमानों के आधार पर दिया जाने की बजाए जैसा कि अब हो रहा है, अब १९७८ के वेतनमानों के आधार पर दिया जायेगा। कम्पनी के क्वार्टरों के लिए मकान किराये में वृद्धि नहीं होगी यानि रिकवरी १९७० के वेतनमानों के आधार पर होगी।

प्रबन्धकों ने निम्न लाभ भी देने का प्रस्ताव पेश किया है :

१. मजदूरों को कम-से-कम गारंटिड लाभ ५० रुपये और नए वेतनमानों पर एक वार्षिक वृद्धि।

२. रात्रि शिफ्ट (रात दस बजे से सुबह छः बजे तक) के किए जाने वाले काम के लिये एक रुपया प्रति रात्रि शिफ्ट भत्ता।

३. समझौते के चार सालों के दौरान करीब १०, ००० मकान बनाए जाएंगे।

लेकिन प्रबंधकों ने समझौते को एक सितंबर १९८२ से लागू करना अभी तक स्वीकार नहीं किया है। ट्रेड यूनियनों ने यह साफ कर दिया है कि वे तब तक समझौते पर दस्तखत नही करेंगी जब तक इसे एक सितम्बर १९८२ से लागू करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रबंधक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नए भर्ती होने वाले मजदूरों को वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी और गारंटीशुदा न्यूनतम लाभ केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही दिया जाएगा। ट्रेड यूनियनों ने प्रबंधकों के इस प्रस्ताव को एकदम अस्वीकार कर दिया है।

प्रबंधकों ने एक आश्चर्यजनक तर्क दिया कि इस्पात उद्योग में न्यूनतम वेतन १५वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तय किये गए नियमों के आधार पर जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन से पहले ही अधिक है। सीटू व अन्य ट्रेड यूनियनों ने प्रबंधकों के दावे का खंडन किया और बताया कि उद्योग में न्यूनतम वेतन जरूरत के आधार पर न्यूनतम वेतन से बहुत ही कम है। प्रबंधकों के प्रस्ताव मजदूरों की उम्मीदों से काफी कम हैं और प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित तुच्छ राशि पर कोई समझौता नहीं होगा।

वर्ष १९६० के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति प्वाइंट वृद्धि पर १ रु० ३० पै. की मौजूदा मंहगाई भत्ते की दर इस्पात मजदूरों के जीवन में लगातार कमी ला रही है और ट्रेड यूनियनों ने प्रबंधकों को बता दिया हैं कि जीवनयापन के सूचकांक में वृद्धि की पूरी भरपाई देने की गारंटी के लिये मंहगाई भत्ते की दर बढ़ाई जाए।

हालांकि प्रबंधक वार्ताओं के दौरान बी पी ई के निर्देशों का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन वे वास्तव में उनका पालन करते हैं और प्रबंधकों के मौजूदा प्रस्ताव बी पी ई के निर्देशों के तहत ही हैं। इन मानकों से ज्यादा देने से प्रबंधकोद्वारा इंकार किये जाने से, स्वभावतः वार्ताओं में रुकावट आ गई है।

इंटक के नेतृत्व ने हाल ही में बी पी ई के निर्देशों का विरोध किया है और कहा है कि ये निर्देश इंटक पर बाध्य नहीं होंगे। उन्होंने वेतन को उत्पादन में भ.वी वृद्धि के साथ जोड़ने तथा समझौतों को पिछली तारीख से ही लागू न करने का विरोध भी किया है। लेकिन उनका यह विरोध मजदूरों को केवल भ्रम में डालने के लिये ही है क्योंकि मजदूरों द्वारा पेश किये गये जायज प्रस्तावों को स्वीकार करने के प्रति प्रबंधकों को मजबूर करने के लिये किसी भी संघर्ष के प्रति इंटकी नेता गंभीर नहीं हैं। यहां तक कि इंटकी नेता मजदूरों के किसी भी आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। इंटक का यह कदम प्रबंधकों की ही इसके लिये सहायता करता है कि वे बी.पी.ई. के निर्देशों को लागू करने के लिए दृढ़ रहें।

प्रबंधकों ने इस्पात उद्योग में हर साल बढ़ रहे ठेका मजदूरों की

(शेष पृष्ठ ३१ पर)

युद्ध के खतरे के खिलाफ विशाल मार्च

भारत के मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता ने अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए गए न्यूक्लीयर युद्ध के खतरे के खिलाफ शांति के लिए विश्वव्यापी संघर्ष में ४ अक्तूबर को देश को सबसे आगे ला दिया है। छः राजनीतिक पार्टियों—सी. पी. आई (एम) सी. पी. आई, आर. एस. पी, फारवर्ड ब्लाक, डी. एस. पी. व पीजेंट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी के आह्वान पर, जिसका सीटू, एटक, यू. टी. यू. सी. व टी. यू. सी. सी. ने समर्थन किया था, देश के हर कोने से ५ लाख लोगों ने नई दिल्ली में बोटक्लब पर रैली में भाग लिया। यह रैली आर्थिक या ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों के लिए नहीं थी बल्कि यह थी युद्ध द्वारा की जाने वाली तबाहियों के खिलाफ तथा प्रगति व विकास की मानवता की महत्वपूर्ण मांग के लिए। मानवता को साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किए गए पिछले दो विश्व युद्धों का अनुभव है। लाखों लाख लोग मारे गए थे, अनेक नगर तबाह कर दिए गए थे। लेकिन अब मजदूर वर्ग के नेतृत्व में विश्व के लाखों लाख मेहनतकश, शांति प्रेमी लोग विश्व प्रभुत्ता की तथा मजदूर वर्ग के नायक—सोवियत संघ व समाजवादी खेमे की तबाही की अमरीकी साजिश को रोकने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता व मजदूर वर्ग भारी संख्या में रैली में शामिल होकर शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल हो गया है। उन्होंने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का झंडा बुलंद किया और फिलिस्तीन, लैटिन अमरीका दक्षिन अफ्रीका व पूंजीवादी दुनिया के युद्धग्रस्त अपने भाइयों के प्रति जो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन—अमरीकी साम्राज्यवादियों के खिलाफ अपने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में जीवन मृत्यु के संग्राम में संघर्षरत हैं, के साथ अपनी एक जुटता व्यक्त की।

राजधानी में शांति मार्च का एक दृश्य

"अमरीकी साम्राज्यवादियों की जंगबाजी मुर्दाबाद," "यहूदीवादी आक्रमणकारी मुर्दाबाद," "न्यूट्रान बम मुर्दाबाद," "और हिरोशिमा नहीं," "और नागासाकी नहीं" के नारों से लालकिले से बोट क्लब तक का मार्ग गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान को हथियार देने बंद करने तथा डिएगो गार्शिया से अमरीकी फौजी अड्डे हटाने की मांग की। मार्च के सबसे आगे एक बड़े बैनर पर अंग्रेजी में लिखा था—"नाभिकीय युद्ध व राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ और फिलिस्तीनी संघर्ष के समर्थन में शांति मार्च।" इसके बाद बैनर था "वाम मोर्चा कमेटी" का। इस मार्च में मजदूर वर्ग, कामकाजी जनता के सभी हिस्सों, किसानों, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों, युवकों, वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, आदि ने भाग लिया। अनेक फिलिस्तीनी छात्रों ने भी इसमें हिस्सा लिया जिनके बैनरों पर लिखा था "रीगन व बेगिन बेरुत नरसंहार के दोषी हैं," "फिलिस्तीनी बच्चों, महिलाओं व वृद्धों के खून को भुलाया नहीं जाएगा।"

जुलूस का पिछला भाग अभी मीलों दूर था कि इधर बोट क्लब पर छः पार्टियों के नेताओं ने भाषण देने शुरू कर दिए। सी पी आई (एम) के बी० टी रणदिवे तथा हरकिशन सिंह सुरजीत ने, सी पी आई से सी० राजेश्वर राव तथा इन्द्रजीत गुप्ता ने आर एस पी से त्रिदिब चौधुरी ने, फारवर्ड ब्लाक से चित्त बसु ने और डी एस पी से एच एन बहुगुणा ने रैली को सम्बोधित किया।

बी टी आर का भाषण

सीटू के अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने कहा कि यहां जो लोग इकट्ठे हुए हैं वे फिलहाल अपने दैनिक संघर्ष को छोड़कर अपना अंतर्राष्ट्रीय कर्त्तव्य निभाने आए हैं। वे शांति के लिए संघष और अपनी सामाजिक व आर्थिक मांगों के लिए संघर्ष में आपसी मेल को समझते हैं। असलियत में, बेहतर वेतन के लिए, मुद्रास्फीति के खिलाफ, रोजगार के लिए, खरीदने की शक्ति में कमी के खिलाफ, बेहतर जीवन

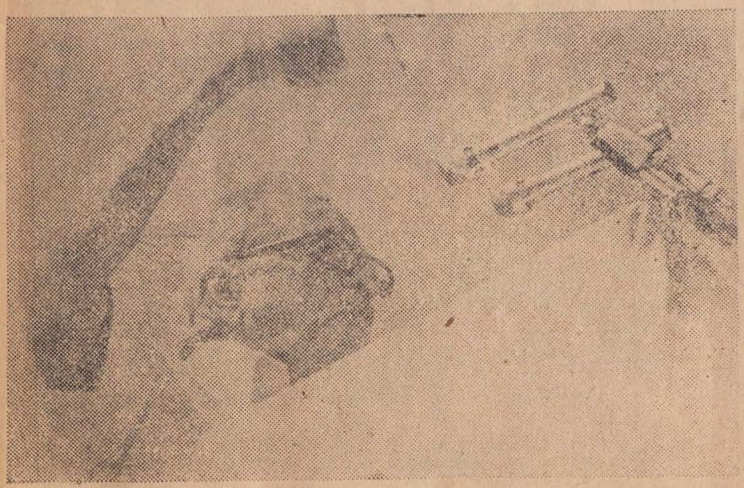

शांति मार्च को सम्बोधित करते हुए बी टी रणदिवे

यापन स्तर के लिए। और एक जनवादी विकल्प के लिए संघर्ष अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी शक्तियों की युद्ध तैयारियों के खिलाफ संघर्ष के साथ जुड़ा है। भारी मुद्रास्फीति व एक करोड़ से भी ज्यादा की बेरोजगारी के साथ गंभीर संकट को दूर करने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादियों ने बाजार-मंडी की प्राप्ति के लिए नाभिकीय युद्ध की तैयारी के लिए अपने फौजी औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया है। और इसका निशाना है इसका सबसे बड़ा दुश्मन—मजदूर वर्ग व समाजवादी खेमा। उन्होंने भारत सरकार की निंदा की कि यह दो महाशक्तियों का शरारतपूर्ण प्रचार करके असल शत्रु अमरीकी साम्राज्यवाद को नजर अंदाज कर रही है और सोवियत संघ को भी अमरीका के साथ एक ही कटघरे में खड़ा कर रही है। उन्होंने शांति के लिए सोवियत संघ के प्रयासों तथा इसकी घोषणा कि यह पहले वार नहीं करेगा की प्रशंसा की। ऐसी घोषणा करने के लिए अमरीका ने साफ मना कर दिया है। युद्ध विरोधी आंदोलनों को तेज करने के लिए मजदूर वर्ग का आह्वान करते हुए बी टी रणदिवे ने कहा कि अंतिम फैसला जनता के हाथ में है न कि अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथ में।

सुरजीत का भाषण

हरकिशन सिंह सुरजीत ने अमरीका की युद्ध तैयारियों तथा विश्व शांति को खतरे में डालने की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल किया कि लेबनान में नरसंहार करने का मुखिया कौन है? नामीबिया व एल सल्वाडोर के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में कौन बाधा डाल रहा है? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को कौन बढ़ावा दे रहा है? अफ्रीकी एकता संगठन में कौन विघ्न डाल रहा है? पाकिस्तान के फौजी शासक को भारी मात्रा में हथियार देकर भारत की दहलीज पर युद्ध का खतरा किसने खड़ा किया है? इन सभी सवालों का जवाब है जनता का दुश्मन—अमरीका। सुरजीत ने सावधान किया कि तेज संघर्षों के बिना भारत सरकार शांति के समर्थन में दृढ़ कदम नहीं उठाएगी और अमरीका को मुख्य शत्रु नहीं कहेगी।

राजेश्वर राव और इंद्रजीत गुप्ता ने जनता का अभिनंदन किया और सोवियत संघ के शांति प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। अमरीकी जंगबाजी की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दो देशों के नजरिए में अंतर उनकी सामाजिक प्रणालियों में अंतर के कारण है। पूंजीवादी प्रणाली में युद्ध आवश्यक है जबकि समाजवाद शांति व जनवाद के लिए है। अन्य वक्ताओं ने भी भारत सरकार के दो महाशक्ति के सिद्धांत की निंदा की और अमरीकी साम्राज्यवाद को बेनकाब करने तथा जंगबाजी के खिलाफ संघर्ष को तेज करने के लिए जनता का आह्वान किया।

शांति के लिए व रीगन-बेगिन गठबंधन के खिलाफ गगनभेदी नारों के साथ रैली समाप्त हुई।

रैली के बाद एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें ई एम एस नंबूदिरिपाद (सी पी आई-एम), सी राजेश्वर राव (सी पी आई), चित्त

बसु, (एफ० बी०), त्रिदिब चौधरी (आर एस पी) व एच एन बहुगुणा (डी एस पी) शामिल थे, उपराष्ट्रपति से मिला और नीचे दिया गया ज्ञापन दिया।

शांति मार्च का ज्ञापन

अमरीकी साम्राजी और उनके सहयोगी दुनिया को नाभिकीय युद्ध की विभीषिका में धकेलने में लगे हैं। इससे पहले कभी युद्ध का खतरा इस तरह सिर पर नहीं मंडरा रहा था जैसे कि आज मंडरा रहा हैं। इससे पहले कभी साम्राजी युद्धपिपासु इस कदर सक्रिय नहीं थे जिस तरह वे आज दुनिया के हर हिस्से में सक्रिय हैं और हर जगह तनाव के केन्द्र खड़े कर रहे हैं।

रीगन प्रशासन पश्चिम यूरोपीय देशों को अपनी जमीन पर परशिंग मिसाइलें लगाने के लिए मजबूर कर रहा है और इस तरह समाजवादी देशों की ही नहीं बल्कि अपने नाटो सहयोगियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है। वह अंतरिक्ष को नाभिकीय टकराव के क्षेत्र में बदल रहा है। वह पहले नाभिकीय हमला करके सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों को नष्ट करने की तैयारियां भी कर रहा है। वह नाभिकीय हथियारों की मदद से सीमित "नाभिकीय युद्ध" चलाने की बातें कर रहा है। यह सरासर धोखा हैं जिसका मकसद जनता की जागरूकता कम करना है। दुर्भाग्य से अगर कभी नाभिकीय युद्ध फूट पड़ता है तो वह 'सीमित' कभी नही रह सकता। इसकी चपेट में सारी की सारी दुनिया आ जाएगी। धन-जन की अपार क्षति होगी और मानव जाति का भविष्य तक खतरे में पड़ जाएगा।

अमरीकी साम्राज्यवादी अपनी सुरक्षा के लिए तथाकथित सोवियत खतरे का मुकाबला करने की ओट में दुनिया पर काबिज होने की अपनी साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने सहयोगियों से मांग कर रहे हैं कि नाटो कार्रवाइयों के क्षेत्र का विस्तार करके हिन्दमहासागर और फारस की खाड़ी तक ले आयें। पश्चिम एशिया में दखलंदाजी करने के लिए उन्होंने रैपिड डिप्लोयमेंट फोर्स तैयार की है और दिएगो गार्सिया को आधुनिक नौसैनिक अड्डे में तबदील कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका में अड्डे हासिल कर लिए हैं। वे पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई के अड्डे में तबदील करना चाहते हैं। और जिया के फौजी निजाम को बड़े पैमाने पर हथियारबंद कर रहे हैं तथा नाभिकीय शक्ति बनने में उस की मदद कर रहे हैं। अमरीका के समर्थन से इस्राइल ने पी एल ओ तथा लेबनानी प्रगतिशील शक्तियों को खत्म करने के लिये लेबनान पर हमला किया है। इसहमले से अनेक इसदावे की कलई खुल गई हैं कि वे पश्चिम एशिया में शांति के पक्ष में है तथा फिलिस्तीन समस्या का हल निकालना चाहते हैं। इस हमले से जाहिर हो गया है कि उनका असली मकसद फिलिस्तीनी जनता को अपना राज्य कायम करने के अधिकार से वंचित करना और इस्राइली यहूदीवादी शासन को सहयोगी बनाकर तेल-धनी पश्चिम एशिया को अमरीकी नियंत्रण में लाना है। लेबनान में इस्राइली आक्रमणकारियों ने जो जुल्म ढाये हैं और पश्चिम बेरुत में शरणार्थी शिविरों में फिलिस्तीनियों का जो नृशंस नरसंहार किया है, उससे यहूदियों तथा अन्य यूरोपवासियों पर हिटलर के अत्याचारों की याद ताजा हो जाती है।

नाभिकीय हथियारों की दौड़ रोकने, फिर इन हथियारों को कम करते-करते अंततः पूरी तरह खत्म करने के लिए सोवियत संघ बहुत ही तर्क संगत प्रस्ताव रखता आया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महा सभा के पिछले विशेष अधिवेशन में सोवियत संघ ने नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की घोषणा की है। हर शांतिप्रेमी को, भले ही वह किसी भी राजनीतिक विचार का क्यों न हो इस घोषणा को खुले दिल से समर्थन देना चाहिए। अगर अमरीका तथा अन्य नाभिकीय शक्तियां ऐसी ही घोषणा करें तो यही चीज नाभिकीय निरस्त्रीकरण की शुरूआत बन सकती है। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ के दूसरे तर्कसंगत प्रस्तावों को ठुकराने के साथ साथ पहले नाभिकीय हमला न करने की इस पेशकश को भी ठुकरा दिया है। दूसरी ओर वह ऐसे प्रस्ताव कर रहा है जिससे नाभिकीय हथियारों के क्षेत्र में सोवियत संघ पर उसकी बढ़त हो जाए। समानता और समान सुरक्षा के सिद्धांतों में आस्था रखने वाला सोवियत संघ, रीगन के ऐसे असंगत प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकता।

आज, जब मानवता के सिर पर नाभिकीय विभीषिका के काले बादल मंडरा रहे हैं, आशा की एक किरण यह है कि विश्व की जनप्रिय शक्तियां इस खतरे को पहचान रही हैं और उसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। महान विश्व शांति आंदोलन की पृष्ठभूमि में लंदन, पेरिस, बोन, रोम, ब्रूसेल्स, हेलसिंकी के जबरदस्त शांति प्रदर्शन, महिलाओं के शांति मार्च और युद्ध के रुझान पर रोक लगाने का मजदूर वर्ग का बढ़ता हुआ निश्चय आदि आक्रमणकारियों पर जनता की इच्छा का अंकुश लगा सकते हैं। हथियारों की दौड़ तथा नाभिकीय हथियारों के खिलाफ न्यूयार्क में हाल ही में हुआ प्रदर्शन— जिसमें समाज के सभी हिस्सों के १० लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था— दिखाता है कि युद्ध की काली ताकतों के खिलाफ लोकप्रिय शक्तियों की ताकत बढ़ रही है। इसी तरह लेबनान में फिलिस्तीनियों के नरसंहार की बेगिन-शेरोन की नीति के खिलाफ तेल अबीब में हाल ही में हुए प्रदर्शन का भारी महत्व है।

शांति के लिए और नाभिकीय युद्ध के खतरे तथा हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के खिलाफ और फिलिस्तीनी जनता के बहादुरीपूर्ण संघर्ष के समर्थन में खुद हमारे देश में छः पार्टियों के आह्वान पर (जो यह ज्ञापन दे रही रही हैं) हाल ही में कलकत्ता त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, कालीकट, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तम, कुरनूल, बंबई, अहमदाबाद, गौहाटी तथा अन्य स्थानों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं और आज भारत की राजधानी में सबसे विशाल देशव्यापी प्रदर्शन हुआ है। हमारे देश में इससे पहले कभी इतना जबरदस्त शांति आंदोलन नहीं हुआ।

यह संतोष की बात हैं कि हमारे देश ने युद्ध की साम्राजी साजिशों का विरोध किया है और हर मंच से विश्व शांति के पक्ष में

(शेष पृष्ठ ३१ पर)

धनबाद में दिमित्रोव शताब्दी संपन्न

धनबाद जिला ट्रेड यूनियन समन्वय समिति ने ११-१२ सितंबर को इंडियन स्कूल आफ माइंस के हाल में बड़े धूमधाम से दिमित्रोव जन्म शताब्दी का आयोजन किया। यूनियनों द्वारा गठित दिमित्रोव शताब्दी कमेटी ने अपना कार्यक्रम महान अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा नेता की १०० वीं वर्षगांठ, १८ जून १९८२ से ही प्रारम्भ कर दिया था।

कमेटी ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों की मीटिंग करके कार्यकर्त्ताओं को दिमित्रोव की शिक्षाओं तथा आज की परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के बारे में शिक्षित किया। कमेटी ने बढ़ रही तानाशाही तथा युद्ध के खतरे के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने और शांति की रक्षा करने के संदर्भ में दिमित्रोव की शिक्षाओं से मजदूरों को अवगत कराया। कमेटी ने तमाम जगहों पर बैठकों का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

अंतिम कार्यक्रम के रूप में धनबाद में दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजिन किया गया जिसका उद्घाटन मा० क० पा० की बिहार राज्य कमेटी के सचिव गणेश शंकर विद्यार्थी ने २ सितंबर को किया। गोष्ठी के प्रमुख वक्ता थे सीटू के कोषाध्यक्ष एवं सांसद समर मुखर्जी। अन्य वक्ताओं में 'स्वाधीनता' के संपादक तथा मा० क० पा० की प० बंगाल राज्य कमेटी के सदस्य अयोध्या सिंह तथा सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्य पी० के० गांगुली शामिल

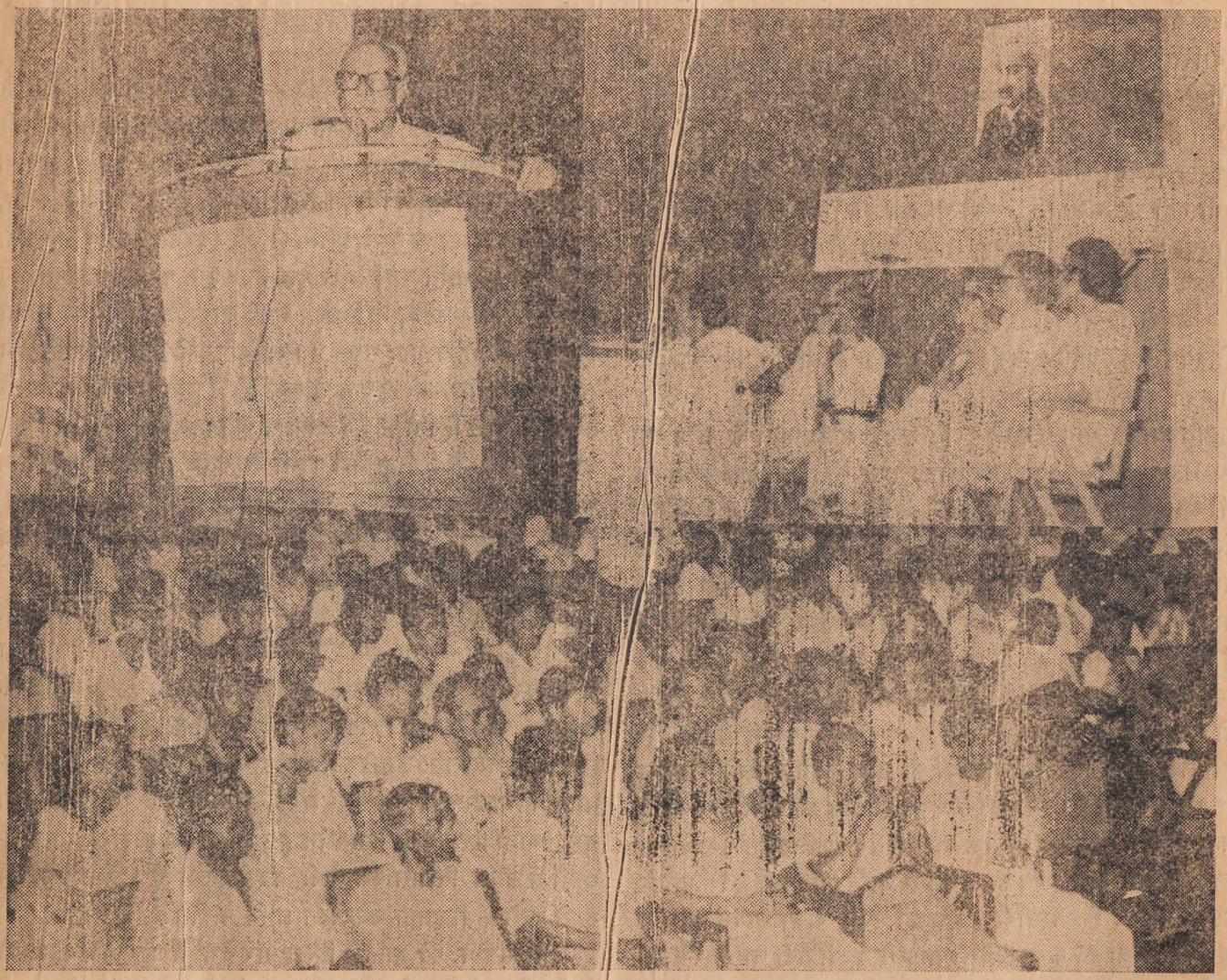

ऊपर : समर मुखर्जी भाषण देते हुए. नीचे : गोष्ठी का एक दृश्य

थे। गोष्ठी में लगभग १००० लोगों ने हिस्सा लिया।

कमेटी के संयोजक यू० एस० चंदा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा गोष्ठी के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने उद्घाटन भाषण में जर्मनी के फासीवादी हमले के खिलाफ विश्व के मजदूर वर्ग तथा कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित करने तथा उस धारा में जनवादी ताकतों को खींच लाने में दिमित्रोव द्वारा अदा की गई भूमिका पर प्रकाश डाला। देश की मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए विद्यार्थी ने देश में बढ़ रहे तानाशाही के खतरे से निपटने के लिये बड़े से बड़े सम्भव मोर्चे के तहत एकजुट होने के लिये मजदूर वर्ग का आह्वान किया। उन्होंने साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ संघर्ष के लिये दिमित्रोव के आह्वान की तरफ मजदूरों का ध्यान दिलाया और अमरीकी साम्राजियों द्वारा पैदा किये जा रहे नाभिकीय युद्ध के खतरे के खिलाफ शांति के लिये संघर्ष में शामिल होने के लिये मजदूरों के सभी हिस्सों से अपील की।

अयोध्या सिंह ने अपने वक्तव्य की शुरूवात प्रेमचंद के उपन्यास से एक उदाहरण देते हुए की जिसमें एक युवक जो महान अक्टूबर क्रांति से काफी प्रभावित था और भारत में अपने साथी मजदूरों को जमींदारों के खिलाफ क्रांति का रास्ता पकड़ने के लिये समझा रहा था। उन्होंने बुलगारिया तथा विश्व में मजदूर आंदोलन को नेतृत्व देने वाले दिमित्रोव की क्रांतिकारी कार्यवाइयों का स्वागत किया। दिमित्रोव ने दो मृत्यु दण्डों से बचकर जर्मनी में शरण ली जहां उन्हें हिटलर के द्वारा संसद में आग लगाने की घटना के मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या सिंह ने साहसपूर्वक कम्युनिस्ट आंदोलन की रक्षा करने और हिटलर के फासीवाद का पर्दाफाश करने में दिमित्रोव की भूमिका की सराहना की। उन्होंने दिमित्रोव के जीवन से सबक लेने तथा उसे इंदिरा सरकार के अधिनायकवाद के खिलाफ संघर्ष में अमल में लाने की अपील की। उन्होंने सम्पूर्ण मानवता तथा सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती देने वाले नाभिकीय युद्ध की तैयारियों के लिये अमरीकी साम्राजियों की निंदा की।

पी० के० गांगुली ने दिमित्रोव के संघर्षमय जीवन का चित्र खींचा जिन्होंने अपने ट्रेड यूनियन जीवन की शुरूवात एक प्रेस मजदूर के रूप में शुरू की तथा अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा के नेता और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के महासचिव चुने गये। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में दिमित्रोव की शिक्षाओं को अपनाया जाना चाहिये। उन्होंने बताया कि फासीवाद तानाशाही तथा अधिनायकवाद अचानक पैदा हो जाने वाली चीजें नहीं हैं और न ही वे अनिवार्य हैं। इसकी पैदाइश लोकतंत्र विरोधी कार्यवाइयों की श्रृंखला के माध्यम से होती है। दिमित्रोव द्वारा विकसित संयुक्त मोर्चे की रणनीति मौजूदा भारतीय परिस्थितियों में भी लागू की जानी है जब कि इन्दिरा शासन के नेतृत्व में अधिनायकवादी ताकतें मजदूर वर्ग पर एक के बाद एक हमले कर रही हैं। एन० एम० ए०, एस्मा० ट्रेड यूनियन-विरोधी काले विधेयक तथा बिहार प्रेस बिल आदि एक के बाद एक लोकतंत्रविरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। यह अनिवार्य है कि मजदूर वर्ग अपनी पांतों को एकजुट कर तमाम लोकतांत्रिक ताकतों को एक करे तथा किसानों और खेतिहार मजदूरों के साथ दृढ़ मैत्री कायम करके सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रत्येक जनवाद विरोधी कदम के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़े। उसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि मजदूर वर्ग समाजवाद और जनतंत्र की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे को ऊंचा उठाए तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों के खिलाफ शांति की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की मुख्यधारा में शामिल हो।

समर मुखर्जी ने प्रारम्भ में ही कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए कमेटी को बधाई दी, जिससे कि धनबाद के मजदूरों को दिमित्रोव की शिक्षाओं से अवगत होने का अवसर मिल सका। उन्होंने अपने विस्तृत भाषण में बताया कि एक वर्गीय समाज में, जहां उत्पादन मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, किस तरह से राज्य सत्ता के सहयोग से मजदूरों का शोषण किया जाता है। ऐसी व्यवस्था में पूंजीपतियों को संवैधानिक तौर पर भी शोषण का अधिकार प्राप्त होता है। साम्राज्यवादी शक्तियां पूंजीवादी व्यवस्था में ही अंतर्निहित संकट पर काबू पाने के लिए औपनिवेशिक शोषण करने के लिए अविकसित देशों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं जिस से उन देशों के मजदूरों का शोषण और भी गहरा होता जाता है। अतः यह पूंजीवादी देशों के मजदूर वर्गों का कर्तव्य है कि वे राज्य-सत्ता से संघर्ष करने के लिए क्रांति का रास्ता अपनायें। परन्तु चूंकि राज्यसत्ता पूंजीपति वर्ग की केन्द्रीकृत शक्ति है अतः मजदूरों को भी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर अपनी पांतों को केन्द्रीकृत करना चाहिए।

मार्क्सवाद लेनिनवाद की यही उपरोक्त धारणा थी जिसे दिमित्रोव ने अपनाया और बुल्गारिया के मजदूरों को क्रांतिकारी बनाने में इसका इस्तेमाल किया। अतः भारतीय संदर्भ में राज्य-सत्ता से संघर्ष करने के लिए मजदूरों और किसानों को मध्यम वर्ग तथा छोटे पूंजीपति वर्ग के साथ एक आदर्श मोर्चा कायम करना होगा। बढ़ रही तानाशाही के खतरे को परास्त करने का एकमात्र रास्ता दिमित्रोव की शिक्षाओं के मुताबिक एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण ही है। समर मुखर्जी ने अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा युद्ध की तैयारियों की निंदा करते हुए इस्राइल द्वारा फिलिस्तीनियों के कत्लेआम में अमरीकी भूमिका की कड़ी आलोचना की और मजदूरों का शांति मार्च में भाग लेने का आह्वान किया।

अन्त में धनबाद जिला समन्वय समिति के सचिव जी० के० बख्शी ने गोष्ठी का समापन किया।

गोष्ठी के बाद विभिन्न संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए।

दिल्ली स्थित बुल्गारियाई दूतावास के माध्यम से दिमित्रोव के जीवन पर आधारित चित्र तथा एक फिल्म भी दिखाई गई।

बी एस एस आर यूनियन ने मानव जाति पर युद्ध के कुप्रभावों से सम्बन्धित चित्रों का प्रदर्शन किया।

कामरेड बी० टी० रणदिवे, इ० एम० एस० नम्बूदिरिपाद,

(शेष पृष्ठ २५ पर)

तोड़फोड़ को पराजित कर सीटू की जयपुर जिला कमेटी बनी

जयपुर के तीन औद्योगिक क्षेत्रों के बहुमत मजदूरों द्वारा सीटू में अपनी आस्था व्यक्त करने तथा जयपुर नगर कमेटी के पुराने नेताओं के समानान्तर संगठन में शामिल हो जाने के साथ ही सीटू की राजस्थान राज्य कमेटी ने जयपुर के लिए कारखानों तथा खदानों से चुने गये प्रतिनिधियों की सीधी हिस्सेदारी के आधार पर सीटू की जिला कमेटी गठित करने का निर्णय लिया।

इस निर्णय के अनुसार २३-२४ अक्तूबर को झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती तथा संसद सदस्य एवं दिल्ली राज्य सीटू के महासचिव सुशील भट्टाचार्य ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। ७४ कारखानों के ३५०० मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ३२१ प्रतिनिधियों तथा १७८ दर्शकों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में ८ कामगार महिलाओं ने भी हिस्सा लिया।

२३ अक्तूबर को तीन बजे सम्मेलन की शुरूआत करते हुए सुशील भट्टाचार्य ने झण्डा फहराया तथा लाल यूनिफार्म में १०० वालंटियरों ने सलामी दी।

सम्मेलन की कार्यवाही के संचालन के लिए का० जमुनाप्रसाद, धर्म पाल और बलबीरसिंह सहित एक अध्यक्षमण्डल का चुनाव किया गया।

कच्ची बस्ती वासियों की एक संगीत पार्टी ने 'शांति का गीत' पेश किया।

स्वागत समिति की तरफ से आर० एम० भटनागर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

शहीदों पर एक प्रस्ताव तथा एक शोक प्रस्ताव पास किया गया और प्रतिनिधियोंने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

नृसिंह चक्रवर्ती ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों का ध्यान उन कठिन परिस्थितियों की तरफ खींचा जिससे होकर भारत का मजदूर वर्ग गुजर रहा है। राजस्थान में सीटू के सदस्यों और समर्थकों की कठिनाइयां तोड़फोड़ के कारण और भी बढ़ गई हैं। जिला कमेटी को मालिकों और सरकार के हमलों से निपटने के साथ साथ तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने सैद्धांतिक प्रचार तथा मजदूरों के हितों के लिये दृढ़ संघर्ष पर जोर दिया।

का० विशम्भर सहाय ने सम्मेलन के संयोजक के रूप में एक रिपोर्ट पेश की।

का० रमेश शर्मा, अमरसिंह और पी० के० पाण्डेय को लेकर प्रस्ताव समिति तथा का० रामपाल और मुखर्जी को लेकर क्रेडेंशियल कमेटी का गठन किया गया।

का० सुशील भट्टाचार्य ने सम्मेलन को सम्बोधित किया। उन्होंने बढ़ रहे युद्ध के खतरे, आई० एम० एफ० कर्ज तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के बढ़ते तानाशाहीपूर्ण हमलों की तरफ सम्मेलन का ध्यान खींचा। उन्होंने इस सरकार द्वारा हड़तालों पर रोक लगाने तथा मजदूर वर्ग के बुनियादी हकों को छीनने के इरादे से लाये गये काले विधेयकों का जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के नजरिए तथा उसकी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीटू कार्यकर्त्ताओं पर हो रहे हमलों के पीछे शासक पार्टी का भी हाथ है। उन्होंने एकजुट होकर हमलों का प्रतिरोध करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया।

प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के बढ़ रहे हमलों का जिक्र किया। का० कंचन शर्मा ने राजस्थान जंगलात विभाग की ग्रास फार्म नर्सरी की महिला कामगारों के साथ बलात्कार करने की कोशिश की घटना तथा नर्सरी लेबर यूनियन के सात नेताओं के उत्पीड़न का जिक्र किया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राजस्थान राज्य कमेटी के सचिव का० हरीराम चौहान ने बिरादराना प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा सीटू के अन्दर ट्रेड यूनियन जनवाद की बहाली के लिए संघर्षरत मजदूरों के साथ अपने समर्थन का इजहार किया।

सीटू की राज्य कमेटी के उपाध्यक्ष का० दुर्गादास शिराली ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया।

सीटू की राज्य कमेटी के सचिव का० प्रेमकिशन शर्मा ने बहस के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गये सवालों का जवाब देते हुए सम्मेलन को सम्बोधित किया।

का० सहाय ने प्रतिनिधियों द्वारा सुझाये गये कुछ मामूली परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए रिपोर्ट को पास करने का प्रस्ताव रखा। प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को पास कर दिया।

का० शर्मा ने कमेटी में प्रत्येक यूनियन से एक प्रतिनिधि के प्रावधान के साथ जयपुर जिला कमेटी के लिए पदाधिकारियों की सूची पेश की। का० विशम्भर सहाय को अध्यक्ष तथा का० पी० के० पांडेय को महासचिव चुनते हुए १७ सदस्यों वाली पदाधिकारियों की सूची को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

अध्यक्ष मण्डल की तरफ से का० धर्मपाल ने वालंटियरों, अतिथियों तथा बिरादराना प्रतिनिधियों को सम्मेलन की सफलता के लिए उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

(शेष पृष्ठ ३१ पर)

पुलिस द्वारा कामगार महिलाओं की पिटाई

राजस्थान में डगोटा झरना सोप स्टोन खदानों के मजदूर प्रबंधकों द्वारा न्यूनतम वेतन कानून के तहत निर्धारित वेतन देने से इन्कार किए जाने के खिलाफ करीब पांच महीनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताल शुरू होने से पहले ६ रुपए दैनिक वेतन और १५ रू० महीना भूमिगत भत्ता देना स्वीकार किया गया था। जब सरकार ने भूमिगत मजदूरों के लिए दैनिक वेतन रू० ६.२५ निर्धारित किया तो प्रबंधकों ने २५ पैसे की वृद्धि करने से इन्कार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने न्यूनतम दैनिक वेतन घटाकर ८·६७ और ५८ पैसे भूमिगत भत्ता कर दिया। अब सरकार ने भूमिगत मजदूरों के वेतन में संशोधन करके इसे रु० १०·२५ दैनिक कर दिया है। लेकिन प्रबंधक यह वेतन देने से इन्कार कर रहे हैं और हड़ताल जारी है।

एन० एच० पी० पी० के सलाल प्रोजेक्ट में प्रबंधक जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निर्धारित वेतन देने से यह कहकर इन्कार कर रहे हैं कि ये वेतन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरों से ज्यादा हैं।

बी० आई० सी० धागा मिल, राजपुरा, पंजाब के प्रबंधक मजदूरों को पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देने से इंकार कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मजदूरों को दिए जाने वाले मामूली लाभों को रूपये की कीमत में आंका जाए और न्यूनतम वेतन घटाए जाएं। लेकिन जब मजदूरों ने यह कटौती मानने से इंकार कर दिया तो प्रबंधकों ने गैरकानूनी तालाबंदी कर दी। इस के साथ ही पुलिस ने प्रबंधकों के हाथों कठपुतली की तरह कार्य करते हुए मजदूरों को निर्दयता से पीटना व आतंकित करना शुरू कर दिया। महिला कामगारों तक को भी नहीं छोड़ा गया। दूसरी ओर उनके ऐसे अंगों को घायल किया गया कि कोई भी सभ्य व्यक्ति पुलिस के व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करेगा।

पंजाब सीटू के अध्यक्ष जगजीत सिंह लायलपुरी और उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, विधायक, २० सितम्बर को पंजाब के मुख्यमन्त्री से मिले और २१ सितम्बर को वित्तमन्त्री ने वार्ता शुरू की। पुलिस जुल्म की जांच कराने की सीटू की मांग को सीधे-सीधे नामंजूर कर दिया गया। हालांकि वित्तमन्त्री ने प्रबन्धकों को कहा कि वे कानून के अनुसार निर्धारित न्यूनतम वेतन की अदायगी करें लेकिन प्रबंधकों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। जे. एस. लायलपुरी और बलवंत सिंह ने मुख्यमंत्री को ३ अक्तूबर को एक बार फिर ज्ञापन दिया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें, लेकिन अभी कोई फल नहीं निकला है।

सीटू केन्द्र के प्रयास

सीटू केन्द्र ने मामले को अपने हाथ में लिया। १० अक्तूबर के पत्र में केन्द्रीय श्रम मन्त्री का ध्यान 'एसियाड केस' में सुप्रीम कोर्ट के १८ सितम्बर १९८२ के फैसले की ओर दिलाया गया जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन से जिन मजदूरों को वंचित रखा जा रहा है वे जबरन मजदूर के सिवाए कुछ नहीं हैं और इन सभी मामलों में संविधान के अनुच्छेद २३ व अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए प्रबंधक दोषी है तथा इसलिए अगर वे न्यूनतम वेतन देने से इंकार करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि पंजाब पुलिस द्वारा महिला कामगारों पर जुल्म की जांच की जानी चाहिए।

सांसदों की राजपुरा यात्रा

सत्य गोपाल मिश्रा, मसुदल हुसैन व जैनाल अबदीन (सभी सी. पी. आई (एम) के सांसद हैं) ११ अक्तूबर को राजपुरा गए। क्योंकि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर डी.सी. वहां मौजूद थे इसलिए वे पहले उनसे मिले और पुलिस दमन के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। डी. सी. ने कहा कि उसके पास अभी तक कोई भी शिकायत लिखित रूप में नहीं आई है। उन्हें यह बताया गया कि बी. आई. सी. धागा मिल के संघर्ष व पुलिस दमन के बारे में लायलपुरी व बलवंत सिंह मुख्यमन्त्री व वित्तमन्त्री से मिल चुके हैं और उनको भी एक लिखित रिपोर्ट दी गई है। डी. सी. ने कहा कि उन्हें यदि लिखित शिकायत की जाएगी तो वे छानबीन करेंगे। बातचीत से यह साफ जाहिर था कि धागा मिल को सरकार से भारी समर्थन प्राप्त है।

सांसदों ने मजदूरों की एक गेट मीटिंग को सम्बोधित किया जिसमें करीब २००० मजदूरों ने भाग लिया। उन्होंने डी. सी. से हुई बातचीत की और अब तक सीटू द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। सांसदों ने शाम को राजपुरा में एक जनसभा को सम्बोधित किया जिसमें ५ हजार से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया।

न्यूनतम वेतन पर सम्मेलन

न्यूनतम वेतन पर एक सम्मेलन ७ नवम्बर १९८२ को कांस्टीच्यूशन क्लब, नई दिल्ली, में आयोजित होगा। इसमें उत्तरप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व मध्यप्रदेश से प्रतिनिधि भाग लेंगे ताकि क्षेत्र में बेहतर न्यूनतम वेतन के लिए संघर्ष शुरू किया जा सके। ▭

सीटू द्वारा बंगाल इम्यूनिटी के राष्ट्रीयकरण की मांग

सीटू के कोषाध्यक्ष एवं संसद सदस्य समर मुखर्जी तथा सीटू सचिव नीरेन घोष के नेतृत्व में बंगाल इम्यूनिटी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष एवं महासचिव सरोज भट्टाचार्य तथा देवव्रत बसु सहित एक प्रतिनिधिमंडल ११ अक्टूबर को केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से दिल्ली में मिला और बंगाल इम्यूनिटी कं०लि० के राष्ट्रीयकरण के सवाल पर बात चीत की।

प्रबंधकों की घोर अकर्मन्तया, व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कट्टर श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण बहुत-सी जीवन-रक्षक दवाओं का निर्माण करने में अग्रणी यह कम्पनी लगभग बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई थी और दो हजार कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। दवा उद्योग के कर्मचारियों के द्वारा वाम मोर्चा सरकार के समर्थन से पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य हिस्सों में व्यापक आन्दोलन किये गये। अन्त में पश्चिम बंगाल सरकार की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने १९७८ में कम्पनी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जो कि इसके राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि के रूप में था। परन्तु तब से मजदूरों द्वारा बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद केन्द्रीय सरकार इस प्रक्रिया में देर करती रही जिस से कुप्रशासन के कारण कारखाने की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं होता रहा है।

केन्द्रीय मंत्री को दिए गये ज्ञापन में यूनियन ने कहा है कि यह देश में एन्टी-टेटनस सीरम पैदा करने वाली एक बड़ी कम्पनी है और इसके साथ में एक अत्यंत कार्यकुशल शोध एवं विकास इकाई भी है जिसने कई अधिक क्षमता वाली पेंसिलिन जैसे जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन तथा अन्य कई जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण करके कम्पनी को काफी नाम दिया है। इस शोध एवं विकास यूनिट ने सीरम निर्माण तथा क्लोरोक्विन फास्फेट के पुनर्मानकीकरण के क्षेत्र में नये आयाम दिए हैं। कम्पनी की बिक्री भी १९७९-८० के ४·३६ करोड़ रुपये से बढ़कर १९८१-८२ में ७·८६ करोड़ रुपये हो गई है। कर्मचारियों के कठिन व सच्चे परिश्रम तथा पूरे दिल से सहयोग करने के कारण ही यह प्रगति संभव हो सकी। इकाई को जीवित रखने में कर्मचारियों ने इस आशा के साथ मदद की थी कि राष्ट्रीयकरण के बाद यह कम्पनी दवा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अग्रणी भूमिका निभाने में अपना पूरा-पूरा योगदान करेगी।

सीटू के महासचिव एवं सांसद पी० राममूर्ति ने इसके बाद १४ अक्तूबर को केन्द्रीय मंत्री को लिखे गये एक पत्र में कम्पनी की जल्द से-जल्द राष्ट्रीयकरण के लिए आग्रह करने के साथ-साथ उनका ध्यान हाथी कमेटी की इस टिप्पणी की ओर भी दिलाया है कि यदि हम अपनी शोध इकाइयों के विकास तथा कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर उचित ध्यान दें तो देश में जीवन-रक्षक और जरूरत के मुताबिक दवाएं पैदा की जा सकती है और इस प्रकार हम आत्मनिर्भरता भी हासिल कर सकते हैं। पुनः उन्होंने हाथी कमेटी की उस सीधी टिप्पणी की ओर ध्यान खीचा है जिसमें उसने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों का जिक्र करते हुए उनके राष्ट्रीकरण की सिफारिश की है। आंकड़ें पेश करते हुए श्री राममूर्ति ने कहा है कि किस तरह से कुप्रशासन के कारण जेंटामाइसिन, विभिन्न सीरम्स और सेलाइन्स आदि जीवन-रक्षक दवाओं का उत्पादन उनकी क्षमतानुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निम्नांकित आंकड़े भी पेश किए हैं जो न केवल मजदूरों की हालत का बयान करते हैं बल्कि कारखाने को सक्षम बनाने में उनके योगदान को भी प्रमाणित करते हैं :—

	१९७८-७९	१९८०-८१	१९८२-८३
आमदनी (लाख रुपयों में)	२९४	७६५	११६९
अन्य निर्धारित व्यय (लाख रुपयों में)	३९	९२	११०
वेतन (आमदनी के प्रतिशत में)	४८-९	३३-९	२३-५

मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वासन दिया कि वे ६ नवम्बर को कलकत्ते में कम्पनी का निरीक्षण करेंगे और सरकार को कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। ▭

इंडियन आक्सीजन के मजदूरों की मांगें पूरी हुईं

इंडियन आक्सीजन वर्क्स मेंस यूनियन (सीटू) ने एक वर्ष के कठोर संघर्ष द्वारा बहुत दिनों से विचाराधीन अपनी मांगों पर समझौता करने के लिए प्रबंधकों को मजबूर कर दिया।

समझौते के अनुसार मजदूरों का न्यूनतम वेतन करीब ९०० रुपये होगा जिसमें १२५ रुपये से लेकर २२५ रुपये तक का लाभ है। अन्य लाभों के साथ-साथ इस समझौते की सबसे प्रशंसनीय बात पेंशन योजना है—जिसे मजदूरों ने भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी योजना के अतिरिक्त हासिल की है। यह त्रिपक्षीय समझौता मुख्यमंत्री ज्योति बसु तथा पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव मनोरंजन राय की उपस्थिति में ८ अक्तूबर को सम्पन्न हुआ। ▭

प्लांटेशन मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन

अखिल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन का चौथा सम्मेलन १६ से १८ सितंबर को सिलिगुड़ी में संपन्न हुआ। सम्मेलन में फिलिस्तनी किसानों की जनरल यूनियन के एक प्रतिनिधि और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पी एल ओ) के नई दिल्ली दूतावास के द्वितीय सचिव के भाग लेने से फिलिस्तीनी जनता व भारतीय मजदूर वर्ग के बीच बिरादराना संबंध मजबूत हुए हैं। और इस प्रकार अमरीकी साम्राज्यवाद के समर्थन से हो रहे यहूदीवादी बर्बर अत्याचार के खिलाफ संघर्षरत पी एल ओ के साथ एकजुटता व्यक्त हुई है। इसके अलावा, बंगलादेश ऐग्रीकल्चरल फार्म लेबर फेडरेशन के महासचिव और सीलेन प्लांटेशन वर्कर्स रेडफ्लैग यूनियन के सचिव की भागीदारी से इन चार देशों के मजदूरों व जनता की दशा को साफ-साफ समझाने में सहायता मिली जिनकी सत्ता अरब देशों में पूंजीवादी क्लिक के हाथों में है और जो यहूदीवादी आक्रमणकारियों के निशाने हैं, बंगला देश में फौजी शासन, श्री लंका में प्रतिक्रियावादी निजाम और भारत में अधिनायकवादी सरकार के हाथों में है। और इससे शांति, जनवाद व समाजवाद के लिए तथा अपने कामन शत्रु, अमरीकी साम्राज्यवाद, के खिलाफ मजदूर वर्ग से संघर्ष को और मजबूत करने में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांत को अपनाने में सहायता मिली है।

सम्मेलन-स्थल पश्चिम बंगाल में होने की वजह से विदेशी प्रतिनिधियों को राज्य की सी पी आई (एम) के नेतृत्व में वाममोर्चा सरकार तथा केन्द्र की सरकार की नीतियों में गुणात्मक अन्तरों को जानने व समझने का अवसर मिला। एक ओर राज्य सरकार बुर्जुवा जमींदार संविधान की जंजीरों के बावजूद जनवादी मूल्यों को बुलंद रखते हुए विकल्प पेश करने की अथक कोशिश कर रही है जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार मजदूर वर्ग के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से अधिनायकवादी तरीके से सभी जनवादी अधिकारों को पैरों के नीचे कुचल रही है। जैसा कि सम्मेलन में हुई बहस से पता चलता है केवल पश्चिम बंगाल व असम के दो राज्यों में बागान मजदूरों की दशा और इनकी सरकारों के नजारिए इस तथ्य के सबूत हैं।

एक ओर पश्चिम बंगाल सरकार है और दूसरी ओर असम सरकार है जिसने बोनस के लिए संघर्ष को दबाने के लिए मालिकान व समाज विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करके मजदूरों पर बर्बर अत्याचार किए, और यहां तक कि उनके घरों को जला दिया गया तथा महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वाममोर्चा सरकार के राजनीतिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट कर दिया गया जब यह पता चला कि त्रिपुरा में वाममोर्चा सरकार की स्थापना के बाद बागान मजदूरों की दशा सुधरी है।

इस प्रकार सिलिगुड़ी में संपन्न बागान मजदूरों का सम्मेलन देश में अधिनायकवाद के बढ़ते खतरे के खिलाफ तथा अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा पैदा किए गए युद्ध के खतरे के खिलाफ संघर्ष के लिए वामपंथी व जनवादी ताकतों को मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

पी एल ओ के ताफिक सालेह और अब्दुल करीम मुस्तफा ने सम्मेलन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे फिलिस्तीन की मुक्ति तक संघर्ष जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं।

बंगलादेश के नुरुल अनवर ने बंगलादेश के खेतिहर मजदूरों के दर्दनाक हालात तथा उनके दृढ़ संघर्ष के बारे में बताया। श्री लंका के आर० सांथिरा मोहन ने भारतीय मजदूर वर्ग के अपने ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष की प्रशंसा की और अपनी यूनियन की इसके साथ बिरादराना एकजुटता व्यक्त की।

बी टी आर द्वारा उद्घाटन

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सीटू के अध्यक्ष बी टी रणदिवे ने फिलिस्तीनी जनता की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए पी. एल. ओ. के यहूदीवादी इस्राइल तथा अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ अविचलित संघर्ष की प्रशंसा की। उन्होंने अमरीकी साम्राज्यवादियों को चेतावनी दी कि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यहूदीवादियों को अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल न करें। इतिहास इसका साक्षी है कि मुक्ति योद्धा वे लोग हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। अंतिम जीत इनकी होगी और अंततः आक्रमणकारियों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे युद्ध के खिलाफ व शांति के लिए संघर्ष में शामिल हों और फिलिस्तानी मुक्ति योद्धाओं को पूरा समर्थन दें। उन्होंने प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि वे एक ऐसे राज्य में बैठक कर रहे हैं जहां की जनता ने कांग्रेस (आई) के नेतृत्व वाली अधिनायकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकते हुए लगातार दूसरी बार वाममोर्चा सरकार की स्थापना की है। मजदूर वर्ग को यही राजनीतिक चेतना न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी जनवादी विकल्प के लिए संघर्ष करने के लिए प्राप्त करनी है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के झंडे के नीचे शांति, जनवाद व समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष के प्रति भी प्राप्त करनी है। खासतौर से असम का जिक्र करते हुए, जहां मजदूरों ने पुलिस द्वारा अभूतपूर्व दमन, समाज विरोधी व पृथकतावादी ताकतों के हमलों का सामना किया है, उन्होंने बागान मजदूरों को उनके जुझारू संघर्षों के लिए बधाई दी। उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया कि वे इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं तथा बड़े बागान तथा विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की मांग उठाएं। उन्होंने कहा कि आई. एफ. एफ. कर्ज की शर्तों से हालत और भी बदतर हुई है जिसके कारण मजदूरों व जनता के ट्रेड यूनियन व

(शेष पृष्ठ २४पर)

का मुकाबला करने के लिए अफगानिस्तान में उठाए गये सोवियत बस युद्ध विरोधी दृष्टिकोण का आह्वान नहीं था।

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी...

(पृष्ठ ६ से आगे)

लिए मजबूर किया जा सके। देश के कोयला मजदूरों की १९७९ की अनिश्चितकालीन हड़ताल का अनुभव यही बताता है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम कर्मचारी एकजुट होकर ऐसा ही आंदोलन छेड़ दें तो बी पी ई तथा सरकार के मनसूबों को शिकस्त दी जा सकती है।

यह सम्मेलन सात लाख कोयला मजदूरों को ८ नवंबर १९८२ को एक दिन की हड़ताल पर जाने के लिए उनके फैसले पर बधाई देता है और उनकी मांगों का पूरा समर्थन करता है।

सम्मेलन इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम प्रतिष्ठानों की यूनियनों का आह्वान करता है कि देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर वर्ग की शक्तिशाली आवाज बुलंद करने के लिए वे संघर्ष के निम्नकार्यक्रम को अमल में लाएं।

१. बी पी ई के निर्देशों का विरोध करते हुए और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सामूहिक सौदे के अधिकार की बहाली के समर्थन में ८ नवंबर १९८२ को अखिल भारतीय दिवस बिल्ले लगाकर, प्रदर्शन आयोजित करके और धरने देकर मनाया जाए। इस दिवस की मांगें होंगी :

(अ) सभी वेतन समझौते पिछले समझौते की समाप्ति के अगले दिन से लागू हों।

(ब) समझौतों में केवल १० प्रतिशत वेतन वृद्धि की सीमा समाप्त की जाए और सही सामूहिक सौदेबाजी द्वारा समझौते होने दिए जाएं।

(स) महंगाई भत्ते की १ रु ३० पैसा प्रति प्वाइंट की दर को खत्म करके जीवनयापन मूल्य में बढ़ोतरी की पूरी भरपाई दी जाए।

(द) वेतन समझौतों को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाए।

(य) नए भर्ती होने वालों के लिए कम वेतन का प्रावधान न हो।

(र) बी पी ई को खत्म किया जाए।

(ल) तमाम मजदूर वर्ग विरोधी कानूनों व कदमों को रद्द किया जाए।

इस दिन तमाम यूनियनें कोयला मजदूरों के साथ जो देश भर में इन्हीं मांगों तथा अन्य कुछ मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर होंगे, अपनी एकजुटता का इजहार करेंगी। कोयला खान मजदूरों के समर्थन में पारित किए गए प्रस्ताव सी आई एल के चेयरमैन तथा सरकार के पास भेजे जायेंगे।

२. चूंकि भविष्य में होने वाला संघर्ष बेहद तीखा होगा इसलिए तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी एक होकर सार्वजनिक क्षेत्र में एक दिन की आम हड़ताल की तैयारी शुरू कर दें। अखिल भारतीय स्तर पर हासिल एकता की भावना को निचले स्तर तक ले जाना होगा ताकि सरकार की नीतियों में बदलाव लाने के लिए ऐसी कार्यवाही की जा सके जो एक लंबे और दृढ़ संघर्ष की राह तैयार कर सकें। सम्मेलन राष्ट्रीय अभियान समिति का आह्वान करता देता है कि वह जल्द-से-जल्द हड़ताल की तारीख तय करे।

यह सम्मेलन सार्वजनिक क्षेत्र में ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वे बी पी ई के निर्देशों का प्रतिरोध करने तथा उसे शिकस्त देने और खास तौर से महंगाई की भरपाई के रूप में १ रु० ३० पै० प्रति प्वाइंट की दर थोपने की सरकार की कोशिश के विरोध में मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमलों तथा इजारेदारों और विदेशी कंपनियों के हित में गलत और प्रतिगामी नीतियां लागू करके सार्वजनिक क्षेत्र को बरबाद करने की कोशिश के विरोध में एकजुट होकर डट जाए। यह सम्मेलन निजी क्षेत्र के मजदूर वर्ग और यूनियनों से भी सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन देने की अपील करता है।

इस सम्मेलन को विश्वास है कि देश का मजदूर वर्ग वक्त के तकाजे को समझते हुए सरकार की शर्मनाक मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों को शिकस्त देने और आवश्यकता पर अधारित वेतन तथा बेहतर जीवन स्तर हासिल करने के लिए उठ खड़ा होगा। ▭

प्लांटेशन मजदूरों का सम्मेलन

(पृष्ठ २३ से आगे)

जनवादी अधिकारों पर हमले बढ़े हैं तथा कड़े कानून व काले विधेयक लागू किए गए है।

रिपोर्ट

आनंद पाठक, महासचिव, द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बागानों की गंभीर हालत पर विस्तार से चर्चा की गई जिसके कारण बंदी, तालाबंदी व छंटनी हो रही है और मजदूरों के संघर्षों पर हमले हो रहे हैं। रिपोर्ट पर हुई बहस में ३०५ में से २५ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुछ संशोधनों के बाद रिपोर्ट अपना ली गई।

विमल रणदिवे, सचिव, ने संगठनात्मक संघर्षों की कुछ कमजोरियों के बारे में बताया और आह्वान किया कि जब एक राज्य में मजदूर संघर्षरत हो तो बाकी सभी राज्यों में एकजुटता कार्यवाहियां होनी चाहिएं।

सम्मेलन में युद्ध के खिलाफ शांति के लिए, फिलिस्तीन पर, आई एम एफ कर्ज और काले विधेयकों के खिलाफ आदि पर प्रस्ताव अपनाए गए।

सम्मेलन के बाद १८ सितंबर को एक जन सभा आयोजित की गई। सभीप के विभिन्न जिलों व बागान क्षेत्रों से मजदूरों ने जुलूसों में आकर जन सभा में हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। अन्यों के अलावा विदेशी प्रतिनिधियों व बी. टी. रणदिवे ने जनसभा को संबोधित किया। ▭

कपड़ा मजदूरों का धरना

पंजाब के मल्हौत, खरड़ व अमृतसर में स्थित ज्यादातर एन. टी. सी. मिलों के करीब ५०० कपड़ा मजदूरों ने ५ अक्तूबर को नई दिल्ली के टालस्टाय मार्ग स्थित (दिल्ली-पंजाब व राजस्थान क्षेत्र के) एन टी सी के दफ्तर के सामने एक दिल का धरना आयोजित किया। दिल्ली व हरियाणा के मजदूर भी वहां मौजूद थे।

पंजाब में कपड़ा मजदूर भेदभाव तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि पहले उद्योग के आधार पर वेतन अवार्ड था, लेकिन उसे पंजाब के कपड़ा मजदूरों पर लागू नहीं किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की १९३८ सीरीज पर आधारित सभी कपड़ा मजदूरों के लिए महगाई भत्ते की प्रणाली भी उनके लिएलागू नहीं की गई। राजस्थान में वेतन दिल्ली की तुलना में कम हैं और पंजाब में वेतन राजस्थान से भी कम है। मामूली सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं दी जाती हैं।

मजदूर इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। खरड़ में १२ सितंबर को संपन्न एक सम्मेलन में धरना आयोजित करने का फैसला किया गया।

इसका अच्छा पहलू यह है कि राष्ट्रीय मजदूर संघ(दारा ग्रुप) ने भी धरने में भाग लिया है।

एन टी सी के चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर को सीटू द्वारा दिये गए ज्ञापन में निम्न मांगें उठाई गईं हैं :

१. एन टी सी के मजदूरों ने अपने सख्त परिश्रम से उद्योग की बीमारी को ठीक कर दिया है और अब इससे कपड़ा उद्योग में उत्पादन के हर स्तर के करीब-करीब समान उत्पादन हो रहा है। इसलिये मजदूरों को वेतन इस उद्योग के कई मिलों में दियेजानेवाले औद्योगिक वेतन के आधार पर दिए जाएं और जहां-जहां जरूरी है वहां सभी स्तरों पर वृद्धि करके सभी फर्कों को खत्म किया जाए। एन टी सी मिलों को बीमार मिल समझा जाने का अब कोई सवाल पैदा नहीं होता।

२. मंहगाई भत्ते के सवाल की भी जल्दी से जल्दी समीक्षा की जानी चाहिये क्योंकि कुछ मिलों में अभी भी १९३९ की सीरीज जारी है जबकि कुछ अन्यों में कोई और फार्मूला लागू किया गया है। अयोध्या टेक्सटाइल्स की प्रणाली सभी जगहों पर लागू की जानी चाहिये।

३. पंजाब में वेतन सबसे कम हैं और इसकी जल्दी से जल्दी समीक्षा की जानी चाहिये :

४. अनेक एन टी सी मिलों में मामूली सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जातीं और निम्न मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए :

(१) मकान किराया भत्ता, (२) कनवेंस भत्ता, (३) शिफ्ट रात्रि ड्यूटी, (४) स्कूटर साइकिल अग्रिम, (५) त्यौहार अग्रिम, (६) सहायता प्राप्तसस्ती कैण्टीन, (७) उपभोक्ता वस्तुओंके लिए उचित दर दुकान, (८) धुलाई भत्ता, (९) छुट्टी यात्रा सुविधा, (१७) २० प्रतिशत बोनस, (११) ड्यूटी पर मुफ्त चाय जैसा कि पंजाब में है।

५. सभी बदली।आकस्मिक मजदूरों को स्थायी किया जाए और २० दिनों तक के न्यूनतम फालबैक वेतन की गारंटी दी जाए।

६. पंजाब में वापस ली गई सालाना व तदर्थ वृद्धि को बहाल किया जाए।

७. उत्पीड़न के सभी मामलों को वापस लिया जाए और छंटनी किए गए मजदूरों को वापस ड्यूटी पर लिया जाए।

८. भ्रष्टाचार की शिकायतों पर यूनियनों के साथ मिलकर छानबीन की जाए और तुरन्त कार्यवाही की जाए।

एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें पंजाब सीटू के अध्यक्ष जगजीतसिंह लायलपुरी, हरियाणा सीटू के महासचिव श्रद्धानन्द सोलंकी व दिल्ली सीटू के दयानंदसिंह शामिल थे, चेयरमैन को एक ज्ञापन दिया और एक घंटे से ज्यादा भी समय तक उस पर बातचीत की। चेयरमैन यह नहीं कह सके कि मांगें नाजायज हैं। उन्होंने केवल यह कहा कि एन टी सी मिल घाटे में चल रहें हैं। जब यह बताया गया कि पंजाब में एन टी सी मिल केवल धागा बनाते हैं और इसलिये इनमें तब तक कोई घाटा नहीं हो सकता जब तक इसमें भारी भ्रष्टाचार न हो, तो चेयरमैन चुप रहे। उन्होंने बताया कि सरकार ने कपड़ा उद्योग पर एक समिति बनाई है और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद ही इन मुद्दों पर कोई फैसला किया जा सकेगा। उन्होंने मजदूरों को ५० रुपये की अतिरिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा जिसे तुरन्त नामंजूर कर दिया गया। मजदूर पक्ष ने कहा कि एन टी सी प्रबंधकों को सालाना वृद्धि व तदर्थ लाभों को वापस नहीं लेना चाहिये था औ उन्हें तुरन्त बहाल किया जाए।

नेताओं ने मजदूरों को चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। एक मत से यह फैसला लिया गया कि यदि प्रबंधक मांगों को मजूर नहीं करते हैं तो संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। ▭

दिमित्रोव शताब्दी ··

(पृष्ठ १९ से आगे)

ज्योति बसु, प्रमोददास गुप्त, नृसिंह चक्रवर्ती तथा बुल्गेरियाई दूतावास के एलेक्जेंडर पेनोव आदि ने शुभकामना संदेश तथा लेख भेजे।

सम्पूर्ण कार्यक्रम ने मजदूरों के अन्दर तानाशाही ताकतों के खिलाफ एकजुट संघर्ष की जुझारू भावना पैदा की। ▭

जूट मजदूरों ने मांग दिवस मनाया

पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार, आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा मेघालय के जूट मजदूरों तथा कर्मचारियों ने आल इंडिया जूट वर्कर्स फेडरेशन (ए. आई. जे. डब्लू एफ.) के आह्वान पर २० सितम्बर १९८२ को "अखिल भारतीय मांग दिवस" मनाया और अपनी मिलों के प्रबन्धकों, संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय श्रम-मंत्री को ७-सूत्री मांगपत्र दिया। विभिन्न जगहों पर रैलियों, गेट मीटिंगों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

२८-२९ अगस्त १९८२ को कलकत्ता में ए. आई. जे. डब्लू. एफ. सी अध्यक्ष डा० (श्रीमती) लक्ष्मी सहगल की अध्यक्षता में संपन्न कार्यकारिणी की बैठक के निर्णय के मुताबिक यह दिवस पूरे देश में तीन लाख से भी अधिक जूट मजदूरों के द्वारा मनाया गया।

फेडरेशन की अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मी सहगल, महासचिव एवं संसद सदस्य नीरेन घोष तथा संयुक्त महासचिव कमल सरकार ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि यदि जूट उद्योग के प्रबंधक—चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में— मजदूरों के सात सूत्री मांग पत्र पर फौरी समझौता नहीं करते हैं तो मजदूरों के पास निकट भविष्य में विरोध हड़ताल की तैयारियां करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा।

मांगें इस प्रकार हैं :—

१. कच्चे जूट के व्यापार तथा जूट निर्मित वस्तुओं के निर्यात सहित समस्त जूट उद्योग का जल्द से जल्द राष्ट्रीयकरण।

२. भारत सरकार कच्चे जूट का समर्थन मूल्य ३०० रुपये प्रति क्विंटल तय करे तथा कच्चे जूट के बाजार में निजी व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाकर सरकारी मशीनरी के माध्यम से परी खरीद करे।

३. १९८१ के लिए २० प्रतिशत बोनस।

४. (अ) उत्तर प्रदेश व असम कोआप्रेटिव जूट मिल्स, मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों में सभी सेवामुक्त मजदूरों को जल्द बहाल किया जाए।

(ख) सरकार सिलहट स्थित सीटू संबद्ध यूनियन कार्यालय को —जिस पर पृथकतावादियों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है— वापस दिलाए तथा अबाध रूप से ट्रेड यूनियन कार्यवाइयों की गारंटी दे।

५. समस्त तालाबन्दियों एवं बन्दियों को वापस लेकर सभी जूट मिलों को बिना शर्त तथा बिना किसी प्रकार का उत्पीड़न किए तथा कार्यभार में वृद्धि किए बिना पुनः खोला जाय तथा तालाबंदी और बन्दी के समय का मुआवजा दिया जाये।

६. जूट मिलों के प्रबंधकों द्वारा हाल में मनमाने तरीके से थोपी गई चार घंटे की उत्पादन कटौती के समय का वेतन दिया जाये।

७. एम० जे० एम० सी० (नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कार्पोरेशन) सहित समस्त जूट मिलें १९७९ के त्रिपक्षीय वेतन समझौतों के अनुसार जूट मजदूरों के लिए वेतनमान एवं वेतनदर संबंधी निर्णयों तथा कार्यभार समिति के निर्णयों को जल्द से जल्द लागू करें। दूसरे राज्यों में स्थित मिलों के प्रबंधक भी इन समझौतों को लागू करें।

एच. एस. सी. एल. कर्मचारियों का आंदोलन

एच० एस० सी. एल० कर्मचारियों ने ४ सितम्बर को दिल्ली में सम्पन्न ज्वाइंट फोरम की बैठक के माध्यम से प्रशासन द्वारा मजदूरों पर काला समझौता थोपने के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का आह्वान एच० एस० सी० एल० यूनियनों की कोआर्डीनेशन कमेटी (सीटू) की तरफ से किया गया था।

ज्वाइंट फोरम की पिछली बैठक में मूल वेतन मंहगाई भत्ता तथा परिवर्वनशील मंहगाई भत्ते से संबंधित प्रबंधकों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव बी० पी० ई० द्वारातय किए गए मानदण्डों से भी कम थे। मजदूर प्रतिनिधियों ने प्रबंधकों से अब तक का सी० पी० सी० मंहगाई भत्ता (सात किस्तें) अदा करने तथा वेतन संशोधन के लिए अन्तिम समझौता होने तक ५० रुपये अंतरिम राहत के साथ उसे जारी रखने की गुजारिश की। प्रबन्धकों ने मजदूर प्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया और मनमाने अन्तिम प्रस्ताव के अनुसार मंहगाई भत्ते की किस्तें अदा करने के बाद अंतरिम राहत को रोक दिया। सीटू यूनियनों ने प्रस्ताव को नामन्जूर कर दिया तथा काले समझौते में शामिल होने से इन्कार कर दिया।

कोआर्डीनेशन कमेटी ने २५ सितम्बर को कलकत्ता में सम्पन्न अपनी बैठक में काले समझौते को खत्म करने, अन्तिम समझौते होने तक देर होने पर केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को मंहगाई भत्ते का भुगतान जारी रखने, तथा मजदूरों की अपूर्ण मांगों पर अन्तिम समझौता होने तक ५० रुपये अन्तरिम राहत की अदायगी जारी रखने आदि मांगों के लिए आंदोलन का कार्यक्रम तय किया। इस कार्यक्रम में पर्चे बांटना, पोस्टर लगाना, ग्रुप मीटिंग, सेक्टर मीटिंग, और बोकारो, भिलाई, विजाग तथा अन्य इकाइयों पर गेट मीटिंगें, प्रशासन को देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभियान, सभी यूनिटों पर ११ से १६ अक्तूबर तक कलकत्ता स्थित मुख्यालय पर धरना आदि शामिल थे।

अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक के खिलाफ सम्मेलन

अस्पताल व अन्य संस्थान विधेयक के खिलाफ एक अखिल भारतीय सम्मेलन १ अक्तूबर को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के फिरोजशाह रोड स्थित हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन का आयोजन आलइंडिया यूनिवर्सिटी एंप्लाईज कनफेडरेशन ने किया था। विभिन्न विश्वविद्यालयों के दो सौ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

कनफेडरेशन के अध्यक्ष जार्ज फर्नांडीस ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

सम्मेलन में सीटू सचिव एम०के०पंधे ने बताया कि यह विधेयक देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन का दमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ही एक हिस्सा है। यह विधेयक अस्पताल व विश्वविद्यालय कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से वंचित रखता है और इन कर्मचारियों पर कार्य व जीवनयापन की मनमानी शर्तें थोपने के लिए अधिकारियों को मनमानी शक्ति देता है। उन्होंने कहा कि सीटू अस्पताल व विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को बुलंद करती है।

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरूण बोस ने सूचना दी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अन्य मांगों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों के तथा विधेयक के खिलाफ मांग के समर्थन में १२ अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ▭

सीटू द्वारा दि० वि० के शिक्षकों व कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन

सीटू के अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे और महासचिव पी० राममूर्ति, सांसद ने १४ अक्तूबर को यह बयान जारी किया :

सेंटर आफ इंडिया ट्रेड यूनियंज दिल्ली विश्वविद्यालय में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इससे पहले ५८ दिनों के लम्बे संघर्ष के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज कर्मचारी यूनियन के साथ १२ फरवरी १९८२ को समझौता हुआ था जिसको लागू करने से वाइस चांसलर द्वारा इन्कार किया जाना उसकी शुरूवात है। पुलिस द्वारा १ अक्तूबर १९८२ को निर्दयता से पिटाई करने और ४५ आंदोलन के नेताओं तथा छात्रों व शिक्षओं के नेताओं को गिरफ्तार किए जाने से स्थिति में बिगड़ाव आने का दूसरा चरण शुरू हुआ। कर्मचारियों के संघर्ष के समर्थन में एक दिन की प्रतिरोध हड़ताल के माध्यम से शिक्षकों द्वारा दी गई चेतावनी पर गौर न करने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के तहत समूचा शिक्षक समुदाय १२ अक्तूबर १९८२ से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गया। वाइस चांसलर द्वारा समझौता करने से जिद्दी इन्कार करने को अनिष्टपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें शिक्षण संस्थानों के स्टाफ के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार और हड़ताल के अधिकार को छीने जाने की झलक दीख पड़ रही है। शिक्षण व गैर शिक्षण स्टाफ ने एकजुट होकर इसका प्रतिरोध करने का फैसला किया है।

सीटू पहले हुए एक समझौते को लागू करने के लिए संघर्षरत विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर बर्बर पुलिस दमन की निंदा करती है।

सीटू दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के संघर्ष का समर्थन करती है और मांग करती है कि पहले समझौते को लागू किया जाए, गिरफ्तार नेताओं को छोड़ा जाए और अन्य मुद्दों पर बिना किसी देरी के समझौता किया जाए। ▭

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए प्रधानमन्त्री निवास के सामने धरना

फेडरेशन आफ मर्केंटाइल एंप्लाईज यूनियंज, कलकत्ता से संबद्ध यूनियनों के करीब १०० कर्मचारियों ने कई बंद जूट मिलों को खोलने की जिनसे ६०,००० मजदूर प्रभावित हैं मांग करते हुए, कई जूट सामंतों द्वारा मजदूरों पर ले आफ थोपने का विरोध करते हुए, जूट उत्पादकों के लिए लाभकारी दामों की मांग करते हुए और उद्योगों में मौजूद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना दिया।

कर्मचारियों ने अपना जुलूस बोट क्लब से शुरू किया और वे अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के निवास पर गए।

सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी, सांसद, ने धरने में भाग लेने वालों को संबोधित करते हुए जूट उद्योग में मौजूद भ्रष्टाचार के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि केंद्रीय सरकार किस प्रकार जूट इजारेदारों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने आह्वान किया कि जूट मजदूरों की जायज मांगों को मानने के प्रति केंद्रीय सरकार को मजबूर करने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना चाहिए।

एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सीटू सचिव एम के पंधे और एफ एम ई यू के महासचिव रामापद चक्रवर्ती शामिल थे, प्रधानमंत्री के सचिव श्री फोतेदार से मिला और जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया जिस पर फेडरेशन द्वारा २६,५५५ मजदूरों से दस्तखत कराए गए थे।

मीटिंग को फिर एम के पंधे, रामापद चक्रवर्ती व एस बी चटर्जी द्वारा संबोधित किया गया। वक्ताओं ने आह्वान किया कि जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा मांगें स्वीकार नहीं की जाती तब तक संघर्ष को जारी रखना चाहिए। ▭

सीटू द्वारा बंबई के मजदूरों पर दमन की निंदा

सीटू के अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे तथा महासचिव एवं सांसद पी० मूर्तिराम ने १२ अक्टूबर को यह बयान जारी किया: सीटू कपड़ा मजदूरों के दीर्घकालीन संघर्ष के समर्थन में ११ अक्तूबर से काम बन्द करने वाले बम्बई के मजदूरों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा छेड़े गये दमन की निन्दा करती है। यह स्थिति भुखभरी का शिकार बनाकर मजदूरों को आत्मसर्पण करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा हड़ताली कपड़ा मजदूरों के नेताओं से बात-चीत करने से हठपूर्वक इंकार करने तथा मजदूरों की हालत के प्रति निर्दयतापूर्ण निश्चिन्तता अपनाने के कारण पैदा हुई है। सरकार ने हड़ताल को दबाने की नाकाम कोशिश में लगभग ११००० से भी ज्यादा मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आवश्यक सुविधाओं के बिना तथा कथित खुली जेलों में रखा जिनके कारण पुन: आंदोलन उठ खड़ा हुआ और उसे दबाने के लिए पुलिस ने मजदूरों पर गोली चलाई।

मौजूद हालात के लिए महाराष्ट्र तथा केन्द्रीय दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। इन्दिरा कांग्रेसी सरकारों ने मजदूरों के संगठन बनाने अपना नेतृत्व चुनने तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों का सम्मान करते हुए बात-चीत के जरिए हड़ताल का समाधान करने की बजाय मजदूरों के ऊपर अपनी पूर्व निधारित नीतियों तथा निर्णयों को थोपने की कोशिश की जिसे मजदूरों ने नामंजूर कर दिया है। ये सरकारें अब दमन के जरिये यह सब थोपने की कोशिश कर रही हैं।

सीटू अपनी महाराष्ट्र राज्य कमेटी के इस अनियंत्रित दमन के खिलाफ १३ अक्तूबर को एक दिन हड़ताल करने के आह्वान का पूरा समर्थन करती है तथा हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपने सदस्यों का आह्वान करती है। सीटू सरकार की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ एकजुटता व्यक्त करने तथा जोरदार आवाज उठाने के लिए अन्य तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करती है।

कपड़ा मजदूरों की हड़ताल में हुई क्षति

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संसद-सदस्य अरविन्द घोष ने ११ अक्तूबर को दिल्ली में सम्पन्न कामर्स कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में बम्बई की कपड़ा मजदूरों की हड़ताल में हुई निम्नांकित भारी क्षति के लिए सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि यह मजदूरों पर इंटक यूनियन थोपने की सरकार की जिद के कारण हुआ है।

कपड़ा उत्पादन में हुई क्षति: ६०० करोड़ रुपये मूल्य का ८६.५ करोड़ मीटर कपड़ा।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों को हुई राजस्व की क्षति: १८० करोड़ रुपये।

मजदूरों को हुई वेतन क्षति: १७० करोड़ रुपये।

६६ प्रभावित मिलों के स्टैंडिंग चार्ज में हुई क्षति: १८० करोड़ रुपये।

कुल क्षति: १४३० करोड़ रुपये।

प्रेस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन

विभिन्न राज्यों से आए हजारों पत्रकारों तथा समाचार पत्र —कर्मचारियों ने २१ अक्तूबर को नई दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन किया। वे समाचार-पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के इरादे से लाए गए बिहार विधेयक की वापसी की मांग कर रहे थे। जुलूस कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित हिन्दुस्तान टाइम्स भवन से शुरू होकर बोट क्लब पहुंचा जहां पर एक रैली हुई। सबसे बड़ा जत्था बिहार से आया था। प्रदर्शनकारी प्रेस विधेयक के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए काले बिल्ले लगाए हुए थे, कुछ अपने मुंह को काली पट्टी से ढके हुए थे और कुछ ने तो अपने मुंह में ताला लगा रखा था। वे "चोरों को बेल (जमानत) पत्रकारों को जेल" नारे से सरकार का मजाक उड़ा रहे थे। रैली कई घंटों तक जारी रही और उसे विभिन्न नेताओं ने सम्बोधित किया। पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह संघर्ष विधेयक वापस लिए जाने तक जारी रहेगा।

भवन निर्माण मजदूरों द्वारा मांग सप्ताह

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन के मजदूरों ने २० से २५ सितम्बर तक मांग सप्ताह मनाया जो कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर विशाल धरने के साथ संपन्न हुआ। इसका आह्वान एन० पी० सी० सी० वर्कर्स यूनियन (सीटू) की तरफ से किया गया। उनकी मांगों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बराबर वेतन, सी० पी० सी० के मुताबिक मंहगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी आदि मांगें शामिल हैं। मजदूरों को अन्यों के अलावा एम० के० पंधे, सचिव (सीटू) ने सम्बोधित किया।

एम० के० पंधे ने मजदूरों की एकता को तोड़ने के लिए सरकार की कोशिशों को एकजुट होकर नाकाम करने के लिए मजदूरों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और कार्पोरेशन मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो और भी तेज और जुझारू आंदोलन छेड़ा जायेगा। उन्होंने मजदूरों की जायज और सही मांगों के लिए सीटू की तरफ से हर सम्भव मदद देने का आश्वासन दिया।

राज्यों के समाचार

उत्तर प्रदेश

चीनी मिल मजदूरों द्वारा संघर्ष की तैयारी

सीटू की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा बुलाई गई सीटू से संबद्ध चीनी मिल मजदूरों की यूनियनों की १७ अक्तूबर को मजहोला में संपन्न एक बैठक में मजदूरों की विभिन्न मांगों के लिए संघर्ष शुरू करने का फैसला लिया गया।

उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में दूसरा वेतन समझौता दिसंबर में खत्म हो जायेगा। मजदूरों को सुविधायें न देने के लिये मालिकान ने पहले से ही नुकसान का गीत गाना शुरू कर दिया है हालांकि उन्हें इस बार भारी मुनाफे हुए हैं। उन्होंने अभी तक गन्ना उत्पादकों को ८० करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है और गन्ने के दाम घटाने व मजदूरों के वेतनमान करने की बात कही हैं। राज्य सीटू ने कहा है कि मालिकान की यह नीति गन्ना उत्पादकों व मिल मजदूरों में फूट डालने के लिये है।

बैठक में १७ यूनियनों के ३३ प्रतिनिधियों ने और हरियाणा के एक प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया तथा मांगपत्र बनाया। बैठक में बदली, मौसमी व आकस्मिक मजदूरों की दशा पर भी विचार किया गया। इन मजदूरों को पी एफ जैसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। मिलों में छंटनी के सवाल पर भी विचार किया गया। संघर्ष करने के सभी यूनियनों के एक-एक प्रतिनिधि के साथ एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जायेगी तथा अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व राज्य अभियान समिति के साथ मिलकर संयुक्त सम्मेलन आयोजित किये जायेंगे।

समापन करते हुए सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने आल इंडिया किसान सभा के साथ तालमेल करने का सुझाव दिया। गन्ना उत्पादकों को लाभकारी दाम देने की मांग मजदूरों द्वारा उठाये जाने का भी उन्होंने सुझाव दिया।

बैठक के बाद एक रैली आयोजित की गई जिसमें सैकड़ों मजदूरों ने हिस्सा लिया। रैली को हरसहाय सिंह, दौलतराम, रविसिंहा, अल्बेल सिंह व नृसिंह चक्रवर्ती ने संबोधित किया।

हरियाणा

हिसार जिला सम्मेलन

हिसार में २५ व २६ सितंबर को सम्पन्न सीटू की हिसार जिला कमेटी के पहले सम्मेलन में १४२ डेलीगेटों व ३३ बिरादराना डेलीगेटों ने भाग लिया। एक अध्यक्षमंडल ने जिसमें अवतार सिंह, राम सिंह, राम कृष्ण, अमीलाल व लाजबीर थे इसकी कार्यवाही चलाई। पृथ्वी सिंह ने झंडा फहराया और राज्य के प्रसिद्ध नेता व राज्य सीटू के उपाध्यक्ष शिवनारायण बैंस ने उदघाटन किया। बैंस ने मजदूरों का आह्वान किया कि वे समय की पुकार के अनुसार अपनी संगठनात्मक मशीनरी को मजबूत करें। और उन्होंने बताया कि पूंजीवादी प्रणाली के संकट को दूर करने के लिए सरकार मजदूरों पर एक के बाद एक हमला कर रही है।

महासचिव टेकचंद गुप्ता ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कांग्रेस (आई) सरकार की श्रमविरोधी नीतियों का विश्लेषण किया। हरियाणा की स्थिति के संबंध में उन्होंने भजनलाल सरकार के जनवाद विरोधी व अवसरवादी चरित्र की निंदा की। सरकारी मशीनरी की सहायता से प्रबन्धकों के गुंडों के हमलों का सामना करते हुए किए गए संघर्षों के लिए उन्होंने मजदूरों की प्रशंसा की। बहस में १५ डेलीगेटों ने भाग लिया। कुछ संशोधनों के बाद रिपोर्ट अपना ली गई। सम्मेलन में युद्ध के खतरे के खिलाफ, इस्राइली आक्रमणकारियों के खिलाफ, १९८२ के चुनावों पर, दमन पर, श्रमविरोधी कानूनों पर, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ, ठेका प्रणाली के खिलाफ, कीमत वृद्धी व बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के लिए लाभकारी दामों पर, बिहार प्रेस विधेयक के खिलाफ, हिसार कपड़ा मिल में पुलिस दमन पर, आई. एम. एफ. ऋण पर, बंबई कपड़ा हड़ताल पर, वाम मोर्चा सरकारों पर, और हिसार व हरियाणा के बिभिन्न उद्योगों में संघर्षों पर प्रस्ताव अपनाए गए।

सम्मेलन को अंत में सीटू की वर्किंग कमेटी के सदस्य एम. एम. लारेंस, एम. पी. ने संबोधित किया। श्रमविरोधी कानूनों, एन. एस. ए. व एस्मा, की निंदा करते हुए उन्होंने भारत सरकार की अधिनायकवादी नीतियों को बेनकाब किया। यह बताते हुए कि किस तरह से तथाकथित राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया था, उन्होंने इंटक की सरकारी नीतियों की पिछलग्गू बनने की निंदा की। सरकारी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने का उन्होंने मजदूरों का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा पैदा किए गए नाभिकीय युद्ध के खतरे के खिलाफ शांति के लिए संघर्ष करें।

सम्मेलन ने एक १५ सदस्यीय जिला कमेटी चुनी जिसके पदाधिकारी इस प्रकार हैं: अध्यक्ष: राम किशन, उपाध्यक्ष: अमीलाल, महासचिव: टेकचंद गुप्ता, संयुक्त सचिव: अवतार सिंह, कोषाध्यक्ष: लाजबीर सिंह।

सम्मेलन के बाद एक रैली हुई जिसे हरियाणा सीटू के उपाध्यक्ष मोहन लाल व एम. एम. ने लारेंस ने सम्बोधित किया।

सीटू प्रत्याशी विजयी

सीटू से संबद्ध लाल झंडा कपड़ा मजदूर एकता यूनियन के श्रीराम इंटक व एटक के उम्मीदवारों को हराते हुए १६ सितम्बर को सम्पन्न हिसार टेक्सटाइल मिल में श्रम निदेशक का चुनाव जीत गए। मजदूरों को आतंकित करने के लिए पुलिस व इंटक के गुंडों की मदद से प्रबन्धकों ने गुंडों को १४ सितम्बर की बैठक में नियुक्त किया। यूनियन के अध्यक्ष अमीलाल व

महासचिव रामबाबू सिंह सहित ८ सीटू कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करके रात भर हवालात में बंद रखा गया और उन्हें सताया गया। लेकिन मजदूरों ने दमन का सामना करते हुए सीटू के उम्मीदवार को भारी बहुमत से विजयी बनाया। जिला सीटू ने पुलिस की गैरकानूनी कार्यवाही की निंदा करते हुए दोषी अफसरान के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ▭

संक्षिप्त समाचार

बैंक एंप्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, ने राज्य सूखा पीड़ितों की सहायता के लिए ५००० रुपये दिये हैं। इसके अलावा बी ई एफ आई के स्थापना सम्मेलन की स्वागत समिति के कोष से भी ५००० रुपये दिए गए हैं।

▭ ▭ ▭

जम्मू कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट वर्कचार्ज एंप्लाईज यूनियन (सीटू) ने प्रबन्धकों को उत्पीड़न तथा जाति व सम्प्रदाय के आधार पर विघटन की नीति की निंदा की है। एक प्रस्ताव में प्रबंधकों की विनाशी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने का फैसला किया गया है।

▭ ▭ ▭

हिमाचल प्रदेश में परवानू की कंक्रीट पोल्ज एंड पेपर कनवर्सन वर्कर्स यूनियन ने रमाल इंडस्ट्रीज वर्कर्स यूनियन तथा सेंटर आफ परवानू ट्रेड यूनियंज के समर्थन से राज्य सरकार से मांग की है कि विभिन्न मांगों के लिए की गई एक घंटे की सांकेतिक हड़ताल के दौरान १० सितंबर को गैरकानूनी ढंग से गिरफ्तार किए गए सभी यूनियन नेताओं को रिहा किया जाए। मजदूरों ने एक दिन का पुलिस थाने पर धरना दिया। अंततः स्थानीय औद्योगिक मजदूरों के तेज संघर्ष के कारण प्रबन्धक मांगों पर समझौता करने के लिए मजबूर हो गए। एक विजयरैली ७ अक्तूबर को सपन्न हुई जिसे सीटू व अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया। ▭

पुरनापानी में २९ सितम्बर को एक विशाल रैली सम्पन्न हुई। इसमें हजारों मजदूरों ने भाग लिया। पन्द्रह ठेका मजदूरों कि छंटनी करने पर प्रबंधकों के खिलाफ २० महीने पुराने संघर्ष की विजय को मनाने के लिए यह रैली हुई जिसे कई सीटू नेताओं ने सम्बोधित किया।

▭ ▭ ▭

सीटू की अमृतसर जिला कमेटी के आह्वान पर हजारों औद्योगिक मजदूरों ने १४ अक्तूबर को अमृतसर नगर निगम के मुख्य इंजीनियर के दफ्तर के सामने रैली आयोजित की। विद्युत सप्लाई में कटौती और उसका मुआवजा देने की मांग करते हुए इसे आयोजित किया गया था। रैली के दबाव में मुख्य इंजीनियर को अपने दफ्तर से बाहर आकर ज्ञापन स्वीकार करना पड़ा।

▭ ▭ ▭

फेडरेशन आफ पुरक एंप्लाईज यूनियन ने जो चार पूर्वी राज्यों के लिए है और जो पुरक विनिमय लिमिटेड के दफ्तर व फील्ड मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रबंधकों को फेडरेशन को मान्यता देने तथा मांग पत्र पर समझौता करने के लिए पटना में २० सितम्बर को मजबूर कर दिया। सभी दफ्तर व फील्ड स्टाफ को १५० रुपए का अतिरिक्त लाभ तथा विशेष वृद्धि व अन्य लाभ मिलेंगे मजदूरों की दैनिक समस्यों पर विचार करने के लिए शिकायत कमेटी भी बनाई गई।

▭ ▭ ▭

आल इंडिया केमिकल एंड फार्मेस्यूटीकल एंप्लाईज फेडरेशन की बिहार ब्रांच के आह्वान पर न्यूनतम वेतन, मंहगाई भत्ते, बोनस, छुट्टी सुविधा, आदि की मांग करते हुए १० अक्तूबर को ५०० दवा मजदूरों ने बिहार के श्रम मंत्रालय के सामने एक रैली की। अध्यक्ष सी एस शर्मा तथा महासचिव चंडीप्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री की गैरहाजिरी में, जो समय देने के बाद भी गैरहाजिर था, एक ज्ञापन श्रम आयुक्त को दिया। मांगों को पूरा कराने के लिए फेडरेशन ने संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है। ▭

मांग पत्र पर समझौते की मांग करते हुए पटना ड्रगिस्ट्स एंड केमिकल वर्कर्स यूनियन (सीटू) ने लाइफ फार्मा एंड कंटीनेटल कैमिकल कम्पनी के खिलाफ संघर्ष शुरूकर दिया है। अन्य यूनियनों की मदद से गेट मीटिंगें लगातार आयोजित की जा रही हैं।

▭ ▭ ▭

इलाहाबाद की ज्वाइंट ट्रेड यूनियन को आर्डिनेशन कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के सामने १ सितम्बर को एक दिन का धरना आयोजित किया। मजदूरों ने सरकार की श्रम विरोधी नीतियों तथा नई दिल्ली में बुलाए गए त्रिपक्षीय सम्मेलन जिसका इंटक को छोड़कर सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने बहिष्कार किया था के खिलाफ प्रतिरोध व्यक्त किया। उन्होंने एन एस ए, एस्मा, ट्रेड यूनियन विरोधी विधेयकों व बिहार प्रेसविधेयक को वापस लेने की मांग की। सीटू, एटक बीएम एस.यूटीयूसी (एल एस), राज्य व केंद्र सरकार कर्मचारियों व अन्य ट्रेड यूनियनों ने धरने में भाग लिया। धरने के दौरान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया।

▭ ▭ ▭

अलीगढ़ में इलेक्ट्रीसिटी एंप्लाईज यूनियन (सीटू) की कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपने १८ सूत्री मांगपत्र के समर्थन १६ अक्तूबर को कासिमपुर पावर हाउस पर सुबह से शाम तक धरना दिया। सीटू की जिला कमेटी के सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रबंधकों से वार्ता के लिए मिला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यूनियन ने २० अक्तूबर से क्रमिक भूख हड़ताल करके संघर्ष को तेज करने का फैसला लिया। ▭

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की कीमत ५० पैसे

सालाना चंदा ६ रुपये

एजेंसी कम से कम ५ प्रतियों की लिखें :

सीटू कार्यालय
६, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-११०००१

बैंक कर्मचारियों का फेडरेशन...

(पृष्ठ १२ से आगे)

खर्च में वर्षों से होने वाली कीमत वृद्धि की पूरी भरपायी न होने के कारण वेतन में आई कमी को पूरा करने के लिए वेतन तथा मंहगाई भत्ते में २५ प्रतिशत की वृद्धि की मांग शामिल है।

प्रस्ताव :—सम्मेलन में बढ़ रहे अधिनायकवाद व केन्द्र सरकार की आर्थिक तथा श्रम नीतियों के खिलाफ, बंबई के कपड़ा व बंगाल के जूट मजदूरों के संघर्ष पर, काले विधेयकों के खिलाफ, ग्रामीण एवं सहकारिता बैंक कर्मचारियों की स्थिति पर, बैंकों में मशीनीकरण व कम्प्यूटर लगाने के खिलाफ, विदेशी तथा अन्य बाकी बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर, तथा अमरीकी साम्राज्यियों द्वारा की जा रही युद्ध की तैयारियों के खिलाफ कई प्रस्ताव पास किए। एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से सम्मेलन ने राष्ट्रीय अभियान समिति के आदेशों का पालन करने का भी निर्णय लिया।

सम्मेलन ने ३२ सदस्यीय केन्द्रीय कमेटी तथा ५२ अन्य लोगों के साथ जनरल काउंसिल का चुनाव किया और निम्न पदाधिकारियों को भी चुना।

अध्यक्ष : नरेश पाल, उपाध्यक्ष : निसार अहमद खान (बिहार), नरेश दास (प० बंगाल) अर्जुन प्रसाद, (उ० प्र०), प्रकाश पाण्डेय (आ० प्र०), महासचिव : आशीष सेन (पश्चिम बंगाल) संयुक्त सचिव : जी० एम० वी० नायक (बंबई), एस०आर० बाल (पश्चिम बंगाल), एस० एन० पाण्डा (उड़ीसा), जी० के० भारद्वाज (दिल्ली), ऊधव ककोती (आसाम), कोषाध्यक्ष : एस० जियाउद्दीन अहमद (प० बंगाल)।

इस्पात वेतन वार्ताएं...

(पृष्ठ १४ से आगे)

समस्याओं का समाधान करने के प्रति कोई रूचि नहीं दिखाई है। इस्पात उद्योग में करीब ७५ हजार ठेका मजदूर कार्यरत हैं और यह संख्या १९७० की संख्या से बहुत ही ज्यादा है। सीटू व अन्य ट्रेड यूनियनें ठेका मजदूरों की वेतनवृद्धि करने पर जोर देती रही हैं लेकिन प्रबंधक उनकी समस्याओं पर कोई भी समझौता करने से बचने के लिये देरदार करने की नीति अपना रहे हैं! इसके कारण प्रबंधकों के साथ सांठगांठ करके निर्मम ठेकेदार इन मजदूरों का लगातार अमानवीय शोषण कर रहे हैं।

सीटू और स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इन्डिया ने बार-बार इस्पात मजदूरों को बताया है कि जब तक समूचे उद्योग में एकजुट संघर्ष नही किया जाता तब तक प्रबंधकों द्वारा उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोकारो सम्मेलन के उद्योग के आधारपर संघर्ष के आह्वान को इस्पात मजदूरों में काफी समर्थन मिल रहा है। हैदराबाद सम्मेलन के फैसलों ने लगातार एकजुट संघर्ष के लिये और भी उत्साह पैदा कर दिया है।

एस. डब्लू. एफ. आई. के पदाधिकारियों की ३० अक्तूबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में द्विपक्षीय वार्ताओं में प्रगति की समीक्षा की जाएगी और उद्योग में एक उचित समझौते के लिए एकजुट कार्यवाही के अगले कार्यक्रम पर फैसला लिया जायेगा।

शांति मार्च का ज्ञापन...

(पृष्ठ १७ से आगे)

अपनी आवाज उठायी है। लेकिन, मानव जाति के सामने मौजूद भारी खतरे को देखते हुए इस सिलसिले में अभी और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। नाभिकीय युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए जनता के सामने साम्राजी साजिशों को बेपर्दा करने के लिए और दुनिया को नाभिकीय तबाही से बचाने के लिए हम, तमाम देशभक्त ताकतों को लामबंद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।

हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह दृढ़ साम्राजविरोधी रुख अपनाये, शांति के लिए सोवियत संघ की पहलों का पूरा-पूरा समर्थन करे और इस संदर्भ में नाभिकीय हथियारों की दौड़ खत्म करने के पक्ष में सशक्त विश्व जनमत के निर्माण के लिए, हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के लिए, दिएगो गार्सिया का अमरीकी अड्डा खत्म किये जाने तथा यह द्वीप मारिशस को लौटाये जाने के लिए, पाकिस्तान के जिया निजाम की भारी हथियारबंदी रुकवाने के लिए, लेबनान पर इस्राइली हमला खत्म किये जाने और फिलिस्तीनी तथा लेबनानी प्रगतिशील शक्तियों का नरसंहार रुकवाने के लिए, अपनी ओर से जरूरी पहल करे। भारत सरकार को फिलिस्तीनी अरब जनता को उसके जायज अधिकार जिनमें अपने स्वतंत्र तथा संप्रभु राज्य की स्थापना का अधिकार भी शामिल है— दिलाने की अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए।

जयपुर जिला कमेटी...

(पृष्ठ २० से आगे)

खुला अधिवेशन

पुलिस ने विघटनकारियों की साजिश से धारा १४४ लगा दी जिसके कारण खुला अधिवेशन सम्मेलन पण्डाल में ही करना पड़ा। यद्यपि खुले अधिवेशन के स्थान परिवर्तन का प्रचार करने के लिए समय नहीं मिल सका। परन्तु फिर भी सैकड़ों मजदूर सभा में शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष का० विशम्भरसहाय ने की तथा का०पी० के० पाण्डेय, आर० एम० भटनागर, प्रेमकिशन शर्मा, सुशील भट्टाचार्य, हरीराम चौहान और नृसिंह चक्रवर्ती आदि ने सभा को संबोधित किया।

नृसिंह चक्रवर्ती और सुशील भट्टाचार्य ने क्रमिक अनशन कर रहे रिक्शा, तांगा तथा स्कूटर चालकों से मुलाकात की और उनके संघर्ष के साथ एकजुटता का इजहार किया।

सीटू द्वारा पी. एल. ओ. को दवा सहायता

सीटू के केन्द्रीय कार्यालय में २२ अक्तूबर को आयोजित एक समारोह में सीटू के कोषाध्यक्ष तथा सांसद समर मुखर्जी ने नई दिल्ली स्थित पी. एल. ओ. दूतावास के द्वितीय सचिव कामरेड अब्दुल करीम मुस्तफा को दवाओं के दो बड़े बक्से तथा ३४०२ रुपये नकद दिये। यह सहायता अमरीका समर्थित इस्राइली हमले के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के बहादुरी पूर्ण संघर्षों के साथ सीटू की एकजुटता स्वरूप दी गयी। समर मुखर्जी ने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अपने संक्षिप्त भाषण में फिलिस्तीनी मुक्ति योद्धाओं की बर्बर हत्याओं के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी तथा यहूदीवादी आक्रमणकारियों की निन्दा की। उन्होंने फिलिस्तीनियों के जुझारू संघर्ष का स्वागत किया और अपनी मातृभूमि के लिए उनकी जायज मांग का पूरा-पूरा समर्थन किया।

अब्दुल करीम ने फिलिस्तीनियों की अन्तिम विजय के अनुकरणीय दृढ़ निश्चय का इजहार करते हुए सन् १९४८ में अमरीकी साम्राजियों की मदद से यहूदी राज्य थोपे जाने के बाद से इस्राइल द्वारा किये जा रहे अमानवीय लूटमार का जिक्र किया। दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के खिलाफ प्रतिक्रियावादी शासकों को इसी प्रकार की आर्थिक एवं हथियारों की मदद देने के लिए उन्होंने अमरीकी साम्राजियों की जोरदार निंदा की। उन्होंने कहा कि पी.एल.ओ. का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया की शान्ति प्रेमी जनता द्वारा दी जा रही मदद से व समर्थन से वे अवश्य ही आक्रमणकारियों को खदेड़ कर अपनी मातृभूमि को प्राप्त करेंगे।

इस अवसर पर सीटू सचिव एम. के. पंधे, नृसिंह चक्रवर्ती तथा सोमनाथ चटर्जी और सुशील भट्टाचार्य सहित अनेक संसद सदस्य भी उपस्थित थे। ▭

सीटू कार्यालय में आई. एल. ओ. अधिकारी का आगमन

आई. एल. ओ. की मजदूर सम्बंध शाखा के श्री जान साइमंड्स २३ अक्तूबर को सीटू कार्यालय में आए और उन्होंने सीटू-सचिव एम. के. पंधे के साथ भारत सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय अभियान समिति की गतिविधियों तथा श्रमिक-शिक्षा के क्षेत्र में सीटू की कार्रवाइयों आदि विषयों पर विचार विमर्श किया।

श्री साइमंड्स जापान में अन्तर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के बाद वापस जेनेवा जा रहे थे। ▭

काम की परिस्थिति तथा पर्यावरण पर विचार गोष्ठी

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) ने सोवियत संघ की ए. यू. सी. सी. टी. यू. तथा संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के सहयोग से बाकू (सोवियत संघ) में ४ से १२ अक्तूबर तक काम की परिस्थितियों तथा पर्यावरण में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यवाई के गठन-विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

सीटू की ओर से गोष्ठी में वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव सुनील बसु राय ने हिस्सा लिया।

उन्होंने गोष्ठी में एक लेख प्रस्तुत किया जिसकी जापान, बंगलादेश, फिलिपाइन, वियतनाम तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने काफी प्रशंसा की। उन्हें भारत बंगलादेश और श्रीलंका ग्रुप का नेता भी चुना गया था। ▭

सीटू नामांकन

सोह्यो और जापान आई. एल. ओ. एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में १५ से २५ नवंबर तक टोकयों में आयोजित होने वाली एशियाई क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन विचार गोष्ठी में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तथा सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी को नामांकित किया गया है।

सीटू ने आई. एल. ओ. द्वारा ४ से ७ नवंबर तक दिल्ली में इंटीग्रेशन आफ पापुलेशन एजुकेशन विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए सीटू की जनरल काउंसिल के सदस्य पी. के. गांगुली को नामांकित किया है। ▭

ए यू सी सी टी यू को बधाई

महान नवम्बर क्रांति की ६५ वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीटू) तथा "सीटू मजदूर" सोवियत संघ की आल यूनियन सेंट्रल काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंस को गर्मजोशी से बधाई देते हैं।

सोवियत संघ के मजदूर वर्ग तथा जनता ए० यू० सी० सी० टी० यू० तथा सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी निर्माण को जारी रखने तथा जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में सफल रहे हैं और इसके साथ ही साथ वे खुल्लमखुल्ला सीमित नाभिकीय युद्ध की बात करने वाले अमरीकी साम्राजियों की उन्माद पूर्ण शस्त्र दौड़ के खिलाफ अपनी सुरक्षा की जरूरतों को भी पूरा करने में सफल रहे हैं। इस घोषणा का कि सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने वाला पहला देश नहीं होगा, दुनिया की तमाम शान्ति प्रेमी जनता ने स्वागत किया है। भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) तथा "सीटू मजदूर" विश्व शान्ति की रक्षा तथा सोवियत जनता की भलाई—दोनों ही कार्यों में सोवियत जतना की सफलता की कामना करते हैं। ▭

एम. के. पंधे द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए ६ तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली-११०००१ फोन : ३८४०७१ से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी-५२-५३, डी डी ए शेड्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, फेज-१, नई दिल्ली-११००२० से मुद्रित